RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ... सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

कोई भी मुर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है- और ज्यादातर मूर्ख करते है।

डेल कार्नेगी

वर्ष-08, अंक - 41 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 30 जुलाई 2026 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

आखिर चूक कहां हुई मोदी सरकार से...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय तक सत्ता शीर्ष पर रहे नरेंद्र मोदी की यह विशेषता रही है कि, वे आम जनता का मूड बहुत जल्दी भाप लेते हैं या जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उनके कई फैसले न केवल सामायिक रहे बल्कि जनभावनानूरूप और अप्रत्याशित भी रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से आहत हुई नई जनरेशन जिसे जेन-जी कहा जाने लगा है। कॉकरोच पार्टी के बैनर तले और सोशल साइट पर घटित हुई कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं को पढ़ने में शायद नरेंद्र मोदी सरकार से चुक हुई और किसान आंदोलन के बाद इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ देश के युवाओं ने किया। हालांकि कई बुद्धिजीवियों का तर्क है कि, सरकार ने जो कार्रवाई आंदोलन के बाद कि वह कार्रवाई नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद तत्काल भी हो सकती थी। जिससे न केवल सरकार की साख बची रह सकती थी, बल्कि युवाओं को भी सड़क पर नहीं उतरना पड़ता।

21 वीं सदी का विरोध प्रदर्शन

सीजेपी का यह आंदोलन पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ा गया और इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य साइडो के ऊपर छोटी-छोटी क्लिप के माध्यम से देश के युवाओं में जोश भरा गया और वो बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध चलाया जा रहा था लेकिन संसद मार्च के दौरान जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उसने देश को झकझोर दिया। मीडिया, विपक्षी दल और आम जनता तक इस अप्रत्याशित कार्रवाई से सत्ते में थी और युवाओं के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। यहां तक की सरकार में भी हलचल होने लगी जिसके बात स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को युवाओं को संबोधित करते हुए एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और उसके बाद सीजेपी को तीनों मांगे मानते हुए सरकार ने अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जिसके बाद सीजेपी ने जश्न मनाते हुए अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी।

क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ अप शब्द जायज है...!

सीजेपी के आंदोलन के बाद देशभर में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। युवाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन को देशभर की जनता ने समर्थन किया था लेकिन आंदोलन के दौरान के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने विशेष कर युवतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। अगर यह वीडियो सही है तो युवाओं का यह आचरण असक्षम है। विरोध प्रदर्शन शालीनता से भी किया जा सकता है हालांकि आंदोलन से जुड़े कई वीडियो युवाओं के देश प्रेम और नारी मर्यादा और स्वच्छता व परोपकार से जुड़े भी है। लेकिन कई वीडियो में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वह ठीक नहीं है। क्या गाली देना आज की फैशन बन गया है...? कई वीडियो में युवा भद्दि-भद्दि गाली देते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार उन पर कोई कार्रवाई करती है तो ईसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए।। सीजेपी की एक मांग यह भी थी कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाए जीसके बाद कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि, गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वालों के केस वापस लिए जाना चाहिए। वहीं अपराधिक पृष्ठभूमि वालों के खिलाब कार्रवाई होनी चाहिए।

क्योंकि, संसद मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस पर भी हमला हुआ था और पुलिस पर हमला छात्र नहीं कोई शातिर अपराधी ही कर सकता है और सीजेपी ने भी माना है कि, उनके शांतिपूर्ण आंदोलन में कुछ अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग घुस गए थे।

चर्चा से ही समाधान

सीजेपी की मांग पर सरकार ने संसद में पेपर लीक रोधी बिल संसद में प्रस्तुत किया जिस पर गतिरोध कायम रहा। जबकि होना यह चाहिए था कि देश के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा कर एक मजबूत व तर्क संगत कानून बनाने पर सहमत होते। जबकि संसद में पक्ष ने पुराने पेपर लिक के मामले गिनाए वहीं विपक्ष उन आरोपों का प्रतिकार करने में ही व्यस्त रहा और सरकार को छात्र आंदोलन के मुद्दे पर ही कोसता रहा। जबकि विपक्ष को चाहिए कि वे सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल का विश्लेषण कर उनमें कमियां निकाल कर सरकार को अवगत कराए जिसमें सरकार एक मजबूत विधेयक पास करा सके।

संसद में चर्चा कम हंगामा ज्यादा

विधानसभाऔं और लोकसभा-राज्यसभा में जनहित के विषयों पर चर्चा से अरुचि और सवालों से बचना एक स्वथ्य लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता हैं। संसद और विधानसभाओं के संचालन में जनता के टैक्स की एक बड़ी रकम खर्च होती है। ऐसे में आम जनता यह उम्मीद करती है कि, लोकतंत्र के इस मंदिर में आम जनता से जुड़े जनहित के मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो। लेकिन हाल ही के दिनों में यह देखने में आया है कि सत्र तय अवधि से भी कम समय चलता है और जितने समय चलता है उसमें चर्चा कम और हंगामा ज्यादा होता है। सत्र की उपयोगिता केवल विधायी कार्य पूरा करने और राजनीति दिखाने भर की रह गई है।

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी तई अवधि से पहले खत्म हो गया जिसमें सरकार ने 15 विधेयक प्रस्तुत कर पारित करवाए लेकिन उन पर सार्थक चर्चा का अभाव रहा। जबकि कई विधयक जनता के जीवन में अहम बदलाव लाने वाले भी थे। सत्ता पक्ष तो यही चाहता है कि, वह जो भी विधेयक प्रस्तुत करें वो पारित हो जाए और सवालों से बचना चाहती है। लेकिन विपक्ष का तो यह दायित्व है कि, सरकार द्वारा लाए गए सभी विधयकों पर सार्थक चर्चा करवाए, सरकार से प्रश्न पूछे और जनहित से जुड़े मुद्दे पर सरकार को चर्चा के लिए बाध्य करें। लेकिन वर्तमान दौर में इसका अभाव देखा जा रहा है और चर्चा से ज्यादा समय हंगामे में में बीत रहा है।

नीट यूज़ी पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 20 हजार पन्नों का आरोपपत्र पेश

नई दिल्ली।

नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में करीब 20 हजार पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र प्रस्तुत किया है।

आरोपपत्र में सैकड़ों दस्तावेज, गवाहों के बयान और भौतिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है।

सीबीआई के अनुसार आरोपपत्र में 422 दस्तावेज, 360 गवाहों की सूची और 43 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि कुछ दस्तावेजों की स्कैनिंग प्रक्रिया अभी जारी है, जिन्हें जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत ने इसके लिए अतिरिक्त समय देने की अनुमति प्रदान की है।

मामले में फिलहाल 13 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के कुछ अधिकारी, कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोग तथा कथित बिचैलिए शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसी ने आरोपियों की भूमिका से जुड़े विभिन्न साक्ष्य भी अदालत के समक्ष रखे हैं।

नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर देशभर में व्यापक चर्चा और विरोध प्रदर्शन हुए थे। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही है। विस्तृत आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अब मामले की सुनवाई महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है और सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला

नई दिल्ली।

छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग की घटना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और महात्मा गांधी के विचारों के विपरीत है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और छात्रों के साथ हुई कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा कि देश में युवाओं और छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। पार्टी ने सरकार से बल प्रयोग की घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वहीं, सरकार की ओर से कहा गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की।

इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को छात्रों के प्रति असंवेदनशील बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों को उचित ठहरा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के खिलाफ जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली।

एक पुराने मानहानि प्रकरण में अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने के कारण अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

मामला एक विवादित बयान से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने कहा कि आरोपी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अथवा कानून के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अदालत के आदेश का सम्मान किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि मामले में विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

उधर, मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि अदालत की कार्यवाही फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है और अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।

गुरु पूर्णिमा: प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गुरु के महत्व और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान करने वाले नहीं होते, बल्कि वे जीवन में सकारात्मक सोच, संस्कार और नैतिक मूल्यों का भी संचार करते हैं।

सामाजिक माध्यम 'एक्स' पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु शिष्यों को सही दिशा दिखाकर समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने सभी से गुरुजनों के आदर्शों को जीवन का आधार बनाने और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया और कहा कि गुरु वह होता है जो व्यक्ति को ज्ञान, सत्य और आत्मविकास का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है और गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव होता है।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन के महत्व को भी रेखांकित किया।

केंद्र सरकार राजनीतिक हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल न करे : सीजेपी

नई दिल्ली।

नागरिक अधिकार संगठन 'सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का उपयोग राजनीतिक हितों के लिए नहीं करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है तथा उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

सीजेपी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग केवल संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। संगठन ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विवादों में बार-बार सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेने से न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और इससे गलत संदेश जाता है।

संगठन ने सरकार से लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवाद के माध्यम से होना चाहिए। न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के राजनीतिक विवाद से दूर रखा जाना आवश्यक है।

सीजेपी ने कहा कि संविधान में सभी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रत्येक संस्था को अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए।

बाढ़ का कहर: एक लाख से अधिक लोग प्रभावित

नई दिल्ली।

ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य के बालासोर, भद्रक, जाजपुर और मयूरभंज जिलों में एक लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन, ओड्राफ, अग्निशमन दल और अन्य बचाव एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पेयजल, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और हालात पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई है, जिससे नदियों के जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है।

सरकार ने लोगों से नदी-नालों के आसपास जाने से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राहत शिविरों में विस्थापित लोगों के लिए भोजन, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन भी शुरू कर दिया गया है।

पति कह रहा मैने बेची गुमटी और पत्नी थाने पहुंची गुमटी चोरी की रिपोर्ट करवाने

माही की गूंज, झाबुआ।

जब पति-पत्नी के मध्य सामान्यजस्य की स्थिति नहीं बनती है तो छोटी-छोटी बात पर होने वाले घरेलू विवाद सड़क तक आ जाते हैं और फिर यह मामले थाने पर पहुंचकर आम चर्चा का विषय बन जाते हैं। इसी तरह पेटलावद क्षेत्र के रायपुरिया में निवासरत पति-पत्नी के बीच पिछले दो-तीन सालों से सामंजस्य नहीं बन पाने के कारण होने वाले छोटे-छोटे विवाद अब सड़क पर मारपीट से लेकर मामले थाने तक पहुंचा है। और बात मारपीट की एफआईआर के साथ अब चोरी की रिपोर्ट तक पहुंच गई है जो रायपुरिया व पेटलावद क्षेत्र में आम चर्चा का विषय बना हुआ है।

कुसुम पाटीदार नाम की महिला पिछले रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि में रायपुरिया बाईपास पर अपनी ही जमीन पर 40 बाय 40 साइज की दो दुकान टीन शेड में बनी हुई थी जो काफी समय से खाली पड़ी थी और वह चोरी हो गई की रिपोर्ट डलवाने रायपुरिया थाने पहुंची।

वहीं कहीं न कहीं रायपुरिया पुलिस पति-पत्नी के मध्य चल रहे विवाद से वाकिफ थी पुलिस ने महिला को चोरी की रिपोर्ट का आवेदन लिखकर दे जाना कह कर वहां से रवाना कर दिया। इस संबंध में जब महिला पक्ष की जानकारी अनुसार मामला माही की गूंज के संज्ञान में आया तो माही की गूंज न्यूज पोर्टल पर ''रातों-रात गायब हुआ 40 बाय 40 का टीन शेड'' शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित किया।

उक्त समाचार का प्रकाशन होने के बाद महिला के पति पूनमचंद पाटीदार के पक्ष की ओर से भी जानकारी आई और पूनमचंद ने बताया कि, उक्त घूमटी मेरी थी और मेरे द्वारा ही बेची गई है। मेरी पत्नी की ओर से झूठी रिपोर्ट थाने में करवाई जा रही है। वहीं पति ने, पति-पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव के संबंध में बताया व पिछले दिनों उसके साथ मारपीट भी हुई बताया।

पूनमचंद पाटीदार ने बताया कि, हम पति-पत्नी के मनमुटाव के चलते करीब पिछले दो वर्षों से मेरा निजी रायपुरिया का घर छोड़कर बामनिया रोड पेट्रोल पंप के पास पेटलावद में टायर पंचर की दुकान करता हूं व रायपुरिया कभी-कभी आना-जाना करता हूं।

पत्नी के साथ अन्य 3 महिलाओ से पिटा हुआ पति।

वहीं 15 जुलाई को मेरी पत्नी कुसुम को मनमुटाव के चलते बातचीत करने हेतु पेटलावद दुकान पर बुलाया था। तथा मेरी पत्नी के पास मेरे जो पैसे पड़े हैं उसमें से लोन भरने हेतु चार लाख रुपए मुझे देने की बात मैंने कही थी। लेकिन मेरी पत्नी के मायके पक्ष की दो-तीन अन्य महिलाओं को साथ लाई और दुकान में पड़े पाने-टामी आदि से मेरे साथ जमकर मारपीट की थी।

इस संबंध में पुलिस थाना पेटलावद में मामला दर्ज करवाया गया था और मुझे कई जगह जख्मी चोटे भी आई थी।

पूनमचंद ने बताया कि, हमारी शादी एक दूसरे के घर में हुई है यानी कि मेरी बहन की शादी मेरे साले के साथ भी हुई है। आपसी रिश्तेदारी में मेरे साथ विवाद किया जा रहा है व मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रायपुरिया स्थित मेरे मकान को हड़पने का प्रयास मेरी पत्नी द्वारा किया जा रहा है। मुझे मारने के बाद मैं रायपुरिया व पेटलावद छोड़कर बाहर आ गया हूं अगर वहां रहूंगा तो मेरी पत्नी व मायके पक्ष वाले मुझे जान से मार देने की संका पूनमचंद जता रहा है।

वही महिलापक्ष के लोगों की चर्चानुसार सामने आ रहा है कि, पूनमचंद नशे व जुए का आदी है और कई बार कमाई पूंजी को खत्म कर चुका है और जब यह लत छोड़ने को कहा जाता है तो घर में दूसरी पत्नी लाऊँगा कहता है। इसलिए घर में मनमुटाव व विवाद चल रहा है।

पूरा मामला माही की गूंज में सामने आने के बाद यही प्रतीत होता है कि, सामाजिक स्तर पर पति-पत्नी की काउंसलिंग कर बच्चों के भविष्य को देखते हुए समझाइस देकर पति-पत्नी व परिवार में आपसी सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। अन्यथा पति-पत्नी के घरेलू विवाद सड़क से लेकर थाने तक आकर अब तक आम चर्चा का विषय बन चुका है जो आने वाले समय में यह विवाद इससे भी बड़ा रूप भी ले सकता है।

इसलिए माही की गूंज भी अपील करता है कि, अब तक हुए जो भी विवाद का सामंजस्य बिठाकर पति-पत्नी के बीच सुलह के प्रयास समाजजन व प्रशासन की और से किये जाना चाहिए।

सीएम ओर किसान नेता आमने-सामने: किसान नेता राकेश टिकेत कल करेंगे सभा

माही की गूंज , पेटलावद।

एक ओर थांदला में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा होनी है तो दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकेत की सभा पेटलावद में होने जा रही है। किसानों की विभिन्न समस्याओ ओर मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पेटलावद में किसान सभा का आयोजन होना है जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ओर किसान नेता राकेश टिकेत विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। यह टिकेत का इस क्षेत्र का पहला दौरा है जिसको लेकर किसानों के उत्साह है। भारतीय किसान यूनियन के स्थानीय नेताओं ने बताया कि किसानों की विभिन्न समस्या जिसमें यूरिया खाद के लिए टोकन सिस्टम बंद करना, फोरलेन निर्माण में जिन किसानों की जमीन जा रही है उनको पर्याप्त मुआवजा दिलवाना, फसल बीमा योजना का लाभ किसानो को दिलवाना सहित किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर अपनी ओर से मांग रखेगे। किसान यूनियन के जितेन्द्र पाटीदार ने अधिक से अधिक किसानो को सभा में पहुंचने के लिए आह्वान किया है। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है को फोरलेन में जिन किसानों की जमीन जा रही है ओर उनको मुआवजा राशि प्रयाप्त नहीं मिली है अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान इस आयोजन के बाद भी ध्यान नहीं देती तो किसान बड़ा इस को लेकर बड़ा आंदोलन की राह पकड़ सकते है,इधर सीएम की सभा में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम लगातार फोरलेन निर्माण को लेकर मैदान में उतरे किसानों के लिए कोई घोषणा करते है या फिर नहीं।

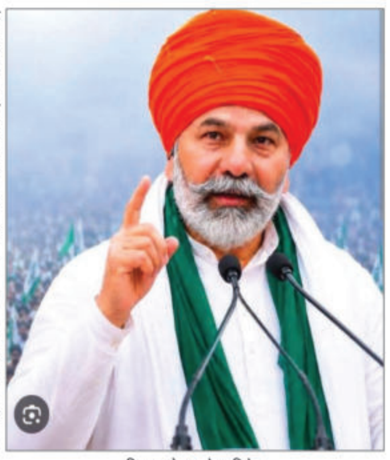
किसान नेता राकेश टिकेत

बारिश से फसलों को संजीवनी, किसानों के चेहरे पर लोटी रौनक

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को आखिरकार भगवान की कृपा से राहत मिली है क्षेत्र में पिछले दो दिन से हो रही रिमझिम वर्षा ने सूखने लगी खरीफ फसलों में नई जान फूक दी है। इस बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी लौट आई है जिससे सोयाबीन, मक्का, उड़द, और अन्य खरीफ फसलों की बडवार फिर से शुरू होने की उम्मीद है। किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसान अत्यधिक चिंतित थे तेज धूप और उमस के चलते खेतों में खड़ी फैसले मर जाने लगी थी और देर से उत्पादन को लेकर आशंकाएं बढ़ गई थी।

फसले खराब होने का था भय

कई किसानों को फसलों के खराब होने का भय सता रहा था लेकिन इस रिमझिम बारिश ने उनकी चिंता काफी हद तक दूर कर दी है। खेतों में पानी की पर्याप्त नमी बनने से फसलों को संजीवनी मिली है जिससेअब अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह समय-समय पर बारिश होती रही तो फसलों का विकास बेहतर होगा और अच्छी पैदावार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं कृषि विशेषग्यो का भी मानना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। बारिश के बाद गांव और खेतों का वातावरण भी खुशनुमा हो गया है खेतों में हरियाली लौटने लगी है और किसानों के चेहरो पर फिर से उम्मीद की मुस्कान दिखाई देने लगी है। समय पर हुई यह बारिश खेती किसानी के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है।

गुजरात पुलिस आई ड्रग्स आरोपी को पकड़ने

माही की गूंज, थांदला ।

एमडी ड्रग्स के मामले में गुजरात की बडौदा पुलिस नगर के दो युवाओं की तलाश में पहुंची थी। जिसमें से एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और एक आरोपी फरार हो गया। मामले की जानकारी देते हुए बड़ौदा पुलिस के एएसआई पीए भेड़ा ओर थांदला टीआई अशोक कनेश ने बताया कि, इसी वर्ष बड़ौदा पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी समीर पठान को पकड़ा था। पुलिस की पूछताछ में समीर ने नगर के जुबेर पिता हसमत पठान से ड्रग्स खरीदना बताया तथा पेसो की लेनदेन विशाल पिता बाबूलाल प्रजापत जो कि एक कियोस्क बैंकिंग ऑपरेटर के मार्फत किए जाने के सबूत मिले है जिसके आधार पर पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। लेकिन जुबेर पठान फरार हो गया विशाल प्रजापत को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। टीआई कनेश ने बताया कि आरोपी ओर विशाल के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर व्हाटसअप पर चैटिंग हिस्ट्री मिली जिसके आधार पर गुजरात पुलिस नगर में आई थी। विशाल प्रजापत को पुलिस साथ ले गई है। जुबेर की तलाश में पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के घरों में भी तलाशी ली है।

इसके पूर्व भी ड्रग्स के मामले में गुजरात पुलिस नगर में दबिश दे चुकी है नगर ड्रग्स तस्कर की शरण स्थली बनता दिखाई दे रहा है। ड्रग्स के एडिक्ट की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जो कि चिंता का विषय भी है।

बिजली कटौती तथा बाल्टेज के उतार चढ़ाव से घरेलू उपकरण जले

माही की गूंज, आम्बुआ।

इन दिनों क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती के कारण बिजली उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर बारिश का मौसम होने से भी अधिक परेशानी हो रही है बार बार अंधेरा होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कीट पतंगों एवं जंगली जानवरों आदि का भय बना रहता है, 28 जुलाई की शाम को बाल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण उपभोक्ताओं के बिजली उपकरण खराब होने के समाचार है।

मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों से क्षेत्र में बिजली कटौती का अघोषित कार्यक्रम चला आ रहा है कभी लोड सैडिंग के नाम पर घंटों बिजली कटौती की जा रही है तो उसके बाद भी कभी भी बिजली गुल हो जाना आम बात है। इतनी कटोती के बाबजूद अनाप-शनाप बिल उपभोक्ताओं को थमाए जाते हैं। बाल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण 18 जुलाई की शाम लगभग 7 से 9 बजे के बीच अनेकों उपभोक्ताओं के घरों में लगे बिजली उपकरण आदि जल जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं।

हमारे प्रतिनिधि को कस्बा क्षेत्र के सैफुद्दीन इब्राहिम तथा मुनबबर हुसैन तैयबजी ने बताया कि, उनके घरों के तथा बोहरा मस्जिद का इनबेटर चार्जर खराब हो गया है। इस तरह कस्बे में बिजली उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं की मांग है कि, बिजली कटौती बंद की जाए , और यदि करना पड़े तो उसका समय निश्चित किया जाए।

संभावित हितग्राहियों की सूची पर चर्चा, शौचालय योजना और वार्ड पंचों की अनुपस्थिति बनी मुद्दा

माही की गूंज, खवासा।

ग्राम पंचायत सेमलिया (नारेला) में बुधवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में सरपंच, उपसरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव सहित पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्राम सभा का मुख्य आकर्षण केंद्र प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की नई सूची रही जिसे देखने और अपने नाम की जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत पहुंचे।

ग्राम पंचायत सचिव ने जानकारी दी कि, 607 संभावित हितग्राहियों की सूची नई तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है उनके नाम नियमानुसार सूची से हटाए जाएंगे। ताकि पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता से प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल सके।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का मुद्दा भी उठा। पंचायत ने कहा कि जिन लोगों ने स्वयं के खर्च पर शौचालय का निर्माण कराया है। वे उसका फोटो एवं आवश्यक दस्तावेज पंचायत में जमा करें। वहीं कई ग्रामीणों ने शिकायत की कि, उन्होंने पहले भी योजना के लिए दस्तावेज जमा किए थे लेकिन अब तक उन्हें कोई लाभ या स्पष्ट जानकारी नहीं मिली।

ग्राम सभा में 20 वार्ड पंचों में से केवल 4 वार्ड पंच उपस्थित रहे। वहीं आवास प्लस सूची को लेकर लगभग 100 से 150 ग्रामीण ग्राम सभा में शामिल हुए।

सूची सार्वजनिक होने के बाद जिन हितग्राहियों के नाम शामिल थे उनमें खुशी का माहौल देखा गया। जबकी जिनका नाम सूची में नहीं था वे निराश दिखाई दिए। ग्रामीणों ने मांग की कि, जिन परिवारों के पास वास्तव में रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र आवास योजना का लाभ दिया जाए।

कांसवा और शर्मा को जिला विद्युत सलाहकार समिति में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

माही की गूंज ,पेटलावद।

झकनावदा नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजेश कॉसवा और पेटलावद मंडल के मंडल महामंत्री विपिन शर्मा को मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर झाबुआ द्वारा गठित जिला विद्युत सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में गठित इस समिति में जिला समिति सदस्य के रूप में मिली जिम्मेदारी को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नियुक्ति की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नगरवासियों में हर्ष का माहौल बन गया और शुभचिंतकों ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दीं। नवीन दायित्व मिलने पर राजेश कॉसवा ने भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो विश्वास उन पर व्यक्त किया है, उस पर वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में विद्युत सेवाओं के सुधार, उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण तथा जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूरी सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। विपिन शर्मा ने कहा को भाजपा संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है अभी तक उसे ईमानदारी से निभाते आए हैं जो भी कार्य इस क्षेत्र में आम जनता के लिए किए जा सकते है उसके लिए तत्पर करुंगा ।

गुरू पूर्णिमा महोत्सव पर निकली कलश यात्रा, जगह-जगह भंडारे का हुआ आयोजन

साईं मंदिर पेटलावद।

माही की गूंज, पेटलावद।

गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए ,गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर नगर सहित पूरे क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा की धूम रही । जगह जगह गुरु पूजन ओर मंदिरों पर गुरु भक्तों की भीड़ देखी गई । पेटलावद नगर में एक साथ कई बड़े आयोजन देखने को मिले , यहां साईं मित्र मंडल द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साईं मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुबह ९रू00 बजे साईं मंदिर से बाबा साईं के मित्र मंडल द्वारा साईं को एक बग्गी मैं साईं की तस्वीर की प्रतिमा रखकर बग्गी में बिठा कर नगर भ्रमण करवाया । इस आयोजन में नगर की छोटी बालिका वो द्वारा अपने सिर पर कलश में नारियल रखकर नगर के मुख्य मार्ग से कलश यात्रा निकाली। यात्रा में भक्त नाचते देखे गए बाबा के जय कारे लगाते रहे। यात्रा मुख्य मार्गो से होती हुई साईं मंदिर पर पहुंची जहां बाबा साईं की महाआरती उतारी गई आरती के बाद साईं मित्र मंडल द्वारा महाप्रसाद भंडारे का आयोजन रखा गया है जहां भक्त लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर भंडारे का भी लाभ लिया। वहीं नगर के गायत्री मंदिर , आशाराम बापू आश्रम, दुलाखेड़ी हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा ,राम शरणम् रामदेव मंदिर सहित कई स्थानों पर हवन ,पूजन के साथ महा आरती, महा प्रसादी के साथ भंडारे का आयोजन नगर के के साथ अन्य स्थानों पर मनाया गया। वहीं बामनिया के समीप पंचमुखी हनुमान, गोदड़िया , कसारबड़ी , सारंगी ,करवड़ सहित कई स्थानों पर गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन ओर भंडारे सम्पन्न हुए।

श्रृंगरेश्व धाम पर हुआ आयोजन, बोलासा में राम शरणम् पर उमड़ी भीड़

पेटलावद विकास खंड के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक मधु कन्या नदी के किनारे बसे श्री श्रृंगरेश्व धाम झकनावदा में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजन किए गए । यहां ब्रह्मलीन काशीगिरी जी महाराज की समाधी पर दर्शन करने के लिए झाबुआ, पेटलावद,धार , राजगढ़ ,सरदारपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अनुयायि शामिल हुए। यहां हवन ,पूजन के पश्चात महाआरती ओर महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। धाम के गादीपति श्री रामेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हुए। बारिश की कमी के चलते इस वर्ष पुराना शिव मंदिर जो कि डूब में जा चुका है, पानी का स्तर कम होने की वजह से शिव भक्तों के लिए खुला रहा जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच कर दर्शन लाभ लिया। वहीं ग्राम बोलासा स्थित श्री राम शरणम् आश्रम पर भी सैकड़ों की भीड़ उमड़ी पर गुरु भक्तों ने गुरु का आशीर्वाद लिया। यहां गुरु भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया।

श्रृंगरेश्वर धाम झकनावदा भंडारा।

कलेक्टर की खवासा में जनसुनवाई, पलवाड़ व पेटलावद क्षेत्र से भी पहुंचे लोग समस्या के समाधान हेतु

माही की गूंज, खवासा।

कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने पंचायत स्तर पर स्वयं द्वारा जनसुनवाई सुनने की व्यवस्था की गई। इसी कड़ी में गत मंगलवार को ग्राम पंचायत खवासा में समस्या के समाधान हेतु कलेक्टर भरसट अपने काफिले के साथ खवासा ग्राम पंचायत पहुंचे। जहां पूर्व निर्धारित जनसुनवाई के चलते ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंच ने सुलभ तरीके से जनसुनवाई में आने वाले लोग, कलेक्टर को अपनी समस्याएं बता सके इस हेतु तमाम व्यवस्थाएं की गई थी।

पंचायत भवन के बाहर जनपद स्तरीय समस्त अधिकारी बैठे एवं तमाम आने वाले आवेदकों के आवेदन की एंट्री पहले बाहर कंप्यूटर में की गई। तत्पश्चात टोकन के साथ ग्राम पंचायत के भवन के अंदर अपने जिला अधिकारियों के साथ बैठे कलेक्टर से एक-एक आवेदक अंदर गए और अपनी समस्याओं को बताया। जिसमें कुछ स्थानीय सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं के साथ राजस्व रिकॉर्ड में भवन एवं जमीनों में त्रुटि सुधार आदि आवेदन भी प्राप्त हुए। जिसमें से कुछ का समाधान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित कर किया और बाकी सभी शिकायतों की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।

खवासा क्षेत्र के सागवा पंचायत के धनपुरा फलिये के ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई कि, स्कूल व हैंडपंप के समीप विद्युत डीपी स्थापित है जिसके चलते हेंडपंप में करंट आने की संभावनाओं के साथ बड़ी दुर्घटना की संभावना जताई। डीपी को हटाकर तालाब किनारे स्थापित किये जाने की मांग पर कलेक्टर ने जांच कर समस्या के समाधान के निर्देश दिए।

खवासा निवासी श्रीमती दितू बिलवाल एवं श्रीमती शकुंतला गोविंद परमार ने किराए के मकान एवं कच्चे एवं जर्जर मकान में निवास करने के चलते प्रधानमंत्री आवास की मांग की।

खवासा के लोगों ने पानी की टंकी से बड़े तालाब स्थित श्मशान घाट तक सीसी रोड की मांग की। उक्त मार्ग पर कीचड़ एवं गड्ढों के कारण बड़ी समस्याओं का समना करना पड़ता है। साथ ही बामनिया-बाजना, खवासा बायपास को स्वीकृति प्रदान की भी मांग की गई।

ढोलखरा से अब तक खवासावासियों को नल-जल योजना का लाभ नहीं मिलने एवं ग्राम में पाईप लाईन के दौरान खोदी गई सड़क में कुछ गलियों में सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है। जहां सड़क निर्माण कार्य करवाने की मांग की।

मकोडिया के अंजू, करण एवं अर्जुन पिता स्वर्गीय सोहन भाभर ने शिकायत में बताया कि, पिता के निधन एवं मां के अन्यत्र विवाह के बाद अपनी दादी का भरण-पोषण कर रहे हैं उनको गरीबी रेखा के अंदर होने के बाद भी खाद्यान्न पर्ची व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

पवन पाटीदार ने अपनी कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख व मौके के नक्शे में अंतर होने के चलते नक्शा दुरुस्ती की मांग की गई।

ग्राम पंचायत भामल के रामसिंह पालरा एवं बबलू पटेल ने कलेक्टर से मांग की कि, तालाब से जो नहर जा रही है वह कच्ची है उसे पक्की बनाई जाए। आदि क्षेत्र की समस्याओं के साथ पलवाड़ क्षेत्र के गामड़ी के ग्रामीणों ने नवापाडा से दौलतपुरा सड़क निर्माण, गांव में अतिरिक्त हेडपंप तथा विद्यालय परिसर में हेडपंप के खनन की मांग की।

वही पेटलावद क्षेत्र के जिन किसानों की भूमि फोरलेन में जा रही है उनके भी प्रतिनिधि मंडल ने आकर कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर उनकी समस्याओं को स्थाई रूप से समाधान करने की मांग की।

जनसुनवाई के तत्पश्चात स्थानीय पत्रकारों को कलेक्टर ने 120 आवेदन प्राप्त होने की बात की। वही पीआरओ ने खवासा जनसुनवाई में 122 आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि की। साथ ही झाबुआ मुख्यालय पर अपर कलेक्टर सी.एस सोलंकी द्वारा ली गई जनसुनवाई में 61 आवेदन प्राप्त होना बताया।

हरिहर आश्रम में पूरे माह होगा आयोजन व नि :शुल्क पार्थिव शिवलिंग का निर्माण

माही की गूंज, बरवेट/बनी।

श्रावण माह 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसी कारण शिव आराधना के लिए सावन माह सबसे उत्तम और विशेष रूप से फलदाई माना जाता हैं। इस पावन माह में पार्थिव शिवलिंग निर्माण को विशिष्ट माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि साधक खुद शिवलिंग का निर्माण करता है और पावन पार्थिव शिवलिंग की पूजा-अर्चना और उसका विषर्जन कर मोक्ष का अधिकारी बनता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से करोड़ों यज्ञों के बराबर फल भी प्राप्त होता है। इसी आस्था को लेकर समीपस्थ ग्राम बनी के हरिहर आश्रम में पूरे माह आयोजन होकर 30 जुलाई से 26 अगस्त तक 27 दिन निःशुल्क पार्थिव शिवलिंग का ग्रामीणों द्वारा हजारो की संख्या में निर्माण कर उनका विसर्जन भागवताचार्य देवेंद्र शास्त्री के सानिध्य में किया जायेगा। वही सावन माह में पड़ने वाली महा शिवरात्रि पर गौशाला में विशेष आयोजन किया जायेगा।

श्रीकृष्ण काम धेनु गौशाला के पीठाधीश्वर आचार्य देवेंद्र शास्त्री धारियाखेड़ी मंदौसर के अनुसार हिंदू धर्म में सावन माह को पवित्र एवं भगवान शिव की भक्ति का महीना माना जाता है। शिव पुराण में भी इसका जिक्र है। मान्यता है कि, सावन माह भगवान शिव का प्रिय माह है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन माह में भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत उसकी पूजा-अर्चना और विसर्जन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री शास्त्री ने बताया कि, पार्थिव शिव लिंग भय से मुक्ति और मोक्ष का माध्यम हैं। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति और व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता के अनुसार पार्थिव पूजन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी देवताओं की पूजन विधियां है, उसमें पार्थिव पूजन के द्वारा शिव की साधना-अराधना ही सबसे आसान और अभीष्ट फल देने वाली है।

भगवान श्री राम ने भी किया था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण

आचार्य श्री शास्त्री ने बताया कि, भगवान श्री राम नें भी लंका पर विजय पाने व रावण के साथ युद्ध करने से पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। श्री राम द्वारा इस पूजा को करने के बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री राम ही नहीं बल्कि न्याय के देवता शनिदेव ने भी सूर्य से अधिक शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव की पूजा की थी। वहीं हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कलियुग में सबसे पहले कूष्मांड ऋषि के बेटे ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना की थी। माना जाता है कि, शिवलिंग का विधिवत पूजन करने से जीवन में सुख, संपत्ति और शान्ति रहती है। साथ ही संतान सुख से वंचित दंपत्तियों की गोद भर जाती है और सभी दुखों से छुटकारा मिलता है।

ऐसे बनाए जाएंगे पार्थिव शिवलिंग

हरिहर आश्रम में वरिष्ठ सदस्य हरिराम पाटीदार (शिक्षक) ने बताया कि, पार्थिव शिवलिंग एक या दो तोला शुद्ध मिट्टी लेकर बनाए जाते हैं। इस शिवलिंग को अंगूठे की नाप का बनाया जाता है। भोग और मोक्ष देने वाले इस पार्थिव शिवलिंग के पूजन को किसी भी नदी, तालाब के किनारे, शिवालय अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर विसर्जन किया जा सकता है। विगत कई वर्षों से सावन माह में यह पर पार्थिव शिवलिंग बनाने का आयोजन निःशुल्क की जाता है। जिसमे क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाभ लेने पहुंचते है।

पहले इन देवों की करते है पूजा

ग्राम बनी के मुकेश पाटीदार ने बताया कि, शिवलिंग बनाने के बाद गणेश जी, विष्णु भगवान, नवग्रह और माता पार्वती आदि का आह्वान कर विधिवत तरीके से षोडशोपचार किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसे परम ब्रम्ह मानकर पूजा और ध्यान करते है। मान्यता के अनुसार पार्थिव शिवलिंग समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सःपरिवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर शास्त्रवत विधि से पूजन करने से परिवार सुखी रहता है।

पार्थिव शिवलिंग की इस तरह की जाएगी पूजा

ग्राम बनी के वरिष्ठ सदस्य बगदीराम पाटीदार ने बताया कि, पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पहले भगवान के सामने बैठकर मन ही मन पूजा का संकल्प पड़ते है। अब किसी साफ जगह पर पवित्र मिट्टी का फूल और चन्दन से शुद्धिकरण करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए इस मिट्टी में गाय का दूध, गाय का गोबर, गुड़, भस्म और गाय के दूध का बना मक्खन बनाकर शिवलिंग का निर्माण करते है। निर्माण करते समय पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके ही शिवलिंग बनाएं जाते है।

वरिष्ठ पत्रकार और ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मनोज जानी को मातृशोक

माही की गूंज ,पेटलावद।

ब्राह्मण समाज के तहसील अध्यक्ष एवं क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार मनोज जानी को मातृशोक हुआ है। स्वर्गीय महेशचंद्र जी जानी की धर्मपत्नी और मनोज जानी की माता जी श्रीमती मनोरमा जानी का दिनांक 24 जुलाई को प्रातः 6 बजे निधन हो गया। श्रीमती जानी के निधन की खबर फैलते ही नगर, समाज और पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा जवाहर मार्ग स्थित निज निवास से निकाली गई, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, प्रबुद्ध जन, समाजजन और बड़ी संख्या में पत्रकार साथी शामिल हुए। उपस्थित सभी लोगों ने नम आंखों से स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा जानी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

आंदोलन में असहज अभिव्यक्तियां और आंदोलन की जीत का श्रेय, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों पर की जाएगी कार्रवाई

माही की गूंज, झाबुआ।

रिंकेश बैरागी

समाप्त हुए आंदोलन से शांति कितनी आई है यह समय चक्र में पता चलेगा कि, यह स्थायी शांति है या अस्थायी ठहराव। हमारा भारत विविधताओं से भरा है, जिसमें राष्ट्र, समाज, जनजीवन, और लोकतंत्र से जुड़े इतने मुद्दे है, जिन्हें संतुलित कर जनहित में आगे बढ़ते रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है। पेपर लीक से जुड़ा यह आंदोलन जिसने सरकार को तीखे रुख दिखाए और अपने आप में मर्यादा को पार किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर, हिंसा प्रदर्शन करने वालों ने देश के युवाओं में भ्रम पैदा किया और विपक्ष और भारत विरोधी शक्तियों ने छात्रों के कंधे पर बंदुक रखकर चलाई।

आंदोलन शुरु हुआ और विपक्ष के साथ-साथ इस आंदोलन में देश विरोधी शक्तियां उभर कर सामने आने लगी। मुद्दों से भटकते हुए आंदोलनकारियों ने धर्म की पटरी बिछा दी, भगवान श्री राम का मजाक बनाया, तो अल्लाह का गुणगान गाया, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे। इतना ही नहीं अपनी सारी मर्यादा लांघ गए छात्रों ने संसद मार्च करते हुए पुलिस के विरोध पर पत्थर बरसाए। हिंसा और विरोध के बीच में राष्ट्र विरोधियों की शक्ति ने युवाओं के साथ मिलकर अराजकता फैलाना शुरु कर दी और इसी आंदोलन के खराब दृश्य को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्यागपत्र सरकार को सौंप दिया।

कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल श्रेय लेने के अपने-अपने प्रयत्न में वांगचूक और अभिजीत दीपके का नाम लेने से परहेज करते रहे। आंदोलन के समय में विपक्षियों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास दिखाई दिया। श्रेय लेने पर टकराव की आहट सबसे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सुनाई दी। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी मौजुद हुए, जिसमें गिरफ्तारी को बड़े संघर्ष के रुप में प्रस्तुत किया गया। अगले दिन संसद में कांग्रेस और सपा के बीच खिंचाव की स्थिति दिखी जिससे उस एकजुटता के प्रदर्शन की हवा निकल गई।

आंदोलन समाप्त होने पर विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ दिखाई दी, विशेष तौर पर कांग्रेस इसका सीधा लाभ लेने के लिए प्रयास में रही। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान आया कि, यह विपक्ष की एकजुटता की शक्ति है जिसने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने कहा कि, उन युवाओं को बधाई जो लोकतंत्र, संविधान और भविष्य की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे। प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी को इसका श्रेय देते हुए कहा कि, वे लंबे समय से छात्रों के जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। उन्होंने इसके लिए एनएसयुआई और यूथ कांग्रेस की भूमिका को भी सराहा। यहां तक की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जीत की मिठाई बांटी गई।

विरोध-प्रतिरोध का अधिकार मौलिक है, किंतु शांतिपूर्ण नागरिक जीवन का अधिकार भी महत्वपूर्ण है। आंदोलन में असहमती के ऐसे तरिकें अपनाने चाहिए जो किसी भी अवरोध को पैदा न करें। आमरण अनशन, सड़क जाम, भड़काउ बयानबाजी भी टकराव को बढ़ाते हुए तार्किक लोकतांत्रिक संवाद को बिगाड़ देती है। जेन-जी की अभिव्यक्तियां भी इस आंदोलन की महत्वपूर्ण पहलु रही। नई पीढ़ी ने हास्य व्यंग्य को आत्मसात करते हुए राजनीतिक संदेशों को व्यंग्य के साथ प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि, संयमी बनों, नकारत्मक नहीं। व्यंग्य और हास परिहास के साथ भाषा की मर्यादा को लांघने वाले जेन-जी को यह पता होना चाहिए कि, सभ्य समाज में अभद्रता और अशिष्टता के लिए कोई स्थान नहीं होता। जेन-जी को आंदोलन के अंदर अभिव्यक्ति और अनादर में अंतर समझना आवश्यक होगा। भाषा में अभद्रता और अशिष्टाचार का उपयोग करके किसी ने भी सभ्य समाज या नए विचार की स्थापना नहीं की है और न ही सभ्य समाज की किसी कुप्रथा को ऐसे तरिके से समाप्त किया जा सकता है।

ध्यान रहे धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र सौंपने से पहले कहा था कि, जंतर-मंतर पर पैदा हुई स्थिति का लाभ राष्ट्रविरोधी ताकतें न उठा लें, इसीलिए वे इस्तिफां सौंप रहे हैं। शिक्षा मंत्री के त्याग पत्र के साथ ही सरकार सीजेपी के संसद मार्च के दौरान की गई हिंसा के जिम्मेदार तत्वों के विरोध में एफआईआर वापस लेने में सहमत हुई उस पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि, क्या हिंसा और उत्पात मचाने वाले अराजक तत्वों को भी छोड़ दिया जाएगा। इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि, सीजेपी के इस आंदोलन में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए निष्पक्ष जांच जरुरी है, और इस जांच में पुलिस पर हमले की जांच भी शामिल होगी। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि, पुलिस दर्ज एफआईआर में जांच जारी रख सकती है, परंतु किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र के विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण नहीं होगा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि, आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वाले अपराधी बचेगें नहीं। आदेश के अनुसार 18 वर्ष से कम बच्चों को साधारण बांड पर तत्काल छोड़े यदि उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों को छोड़ने की मांग कर रही है जबकि सरकार का स्पष्ट है कि जो गैर सामाजिक तत्व अराजकता फैला रहे थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

इस आंदोलन से न केवल जेन-जी बल्कि सभी पीढ़ियों के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए कि, क्या किसी पक्ष के लिए यह जीत के जश्न का अवसर है या फिर सभी के लिए गंभीर आत्मचिंतन का विषय है? पिछले कुछ वर्षों में इतनी परिक्षाओं के पेपर लीक हुए है जिनकी गिनती करना कठिन है। केन्द्रीय परिक्षाओं के साथ राज्यों की परिक्षाओं के भी पेपर लीक हुए है। इसलिए राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाकर मामले की इतिश्रि नहीं कर सकते। सभी को मिलकर समस्या का समाधान करना होगा। क्या पेपर लीक और परिक्षाओं में नकल करना समाज का चारित्रिक और नेतिक पतन नहीं है। क्या किसी सरकार या राजनीतिक दलों, विपक्षी या फिर सीजेपी, के पास समाज के इस चारित्रिक और नेतिक पतन को रोकने उसे जड़ से समाप्त करने का कोई सहज, सरल उपाय है?

हालांकि श्रेय लेने की होड़ ने विपक्षियों की एकजुटता के ऊपर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, और धरनारत छात्रों ने एक सभ्य समाज में रहते हुए अभिव्यक्ति की अपनी भाषा को मर्यादा के पार जाकर अभद्र और अशिष्ट दर्शाकर अनादर किया। बहरहाल, भूल को स्वीकार करना उसे सुधारने की पहली सीढ़ी होती है, गलत के साथ गलत और सही के साथ सही व्यवहार करना चाहिए। दिल्ली में प्रदर्शनकारी भारतीय संसद में घुसना चाहते थे, ताकि पुलिस इन आंदोलनकारियों पर गोलिया चलाए, फिर राष्ट्र विरोधी ताकतें पूरे देश में आगजनी करे और विश्व में भारत सरकार को तानाशाह घोषित करे, परंतु यह होने नहीं दिया गया। युवा देश विरोधी ताकतें, विपक्ष और वामपंथियों के झांसे में न आए, नेरेटीव की इस लड़ाई में जहां सरकार सही है वहां सरकार का पूरा साथ दें।

संपादकीय

इथेनॉल पर सवाल

पेट्रोलियम पदार्थों के विदेशों से आयात पर देश की अत्यधिक निर्भरता हमेशा गंभीर चिंता का विषय रही है। खासकर, हालिया पश्चिम एशिया संकट के दौरान हॉर्मूज खाड़ी में कच्चे तेल व गैस टैंकरों की आवाजाही पर रोक ने स्थिति की गंभीरता को दर्शाया। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल को लेकर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये इसमें इथेनॉल मिलाने का विकल्प चुना। लेकिन आज इसके साइड इफेक्ट को लेकर देश में चिंता बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि इससे वाहनों की माइलेज कम हुई है। कुछ की आशंका है कि गाड़ियों के रखरखाव की लागत बढ़ी है। दरअसल, इसकी वजह इथेनॉल के उपयोग को लेकर किसी प्रामाणिक अध्ययन का सामने न आना भी रहा है। ऐसे में अब जब केंद्र सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि उसने अभी तक ऐसा कोई आकलन नहीं किया है, जिससे पता चल सके कि देश में कितने वाहन ई-20 यानी अस्सी प्रतिशत पेट्रोल व बीस प्रतिशत इथेनॉल के अनुकूल हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इससे यह बात साबित होती है कि देश के हरित ऊर्जा के लक्ष्यों और जमीनी स्तर की तैयारियों के बीच कितना अंतर है। ऐसे में वाहनों की प्रामाणिक गिनती या सर्वे के बिना देशव्यापी बदलाव के सफल होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? निस्संदेह ई-20 को बढ़ावा देने का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन घटाना और भारत की बायोफ्यूल वाली अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाना है। वहीं सरकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर हुए अध्ययनों और फील्ड ट्रायल में यह वैकल्पिक ईंधन निर्धारित मानकों के तहत प्रयोग के लिये सुरक्षित पाया गया है। निस्संदेह, नियंत्रित स्थिति में हुए वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन जब लाखों वाहन चालकों को प्रभावित करने वाली किसी नीति का क्रियान्वयन किया जाता है तो जनता का विश्वास हासिल करने के लिये प्रामाणिक डेटा की भी जरूरत होती है।

बहरहाल, संसद में सरकार की स्वीकारोक्ति से इस नीति को लेकर विरोधाभास तो उजागर होता ही है। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ सालों से बीस करोड़ दुपहिया वाहनों और तीन करोड़ से ज्यादा पेट्रोल से चलने वाली कारों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी दलील है कि इसके बावजूद कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। हालांकि, सरकार की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि जिन वाहनों को लेकर वह दावा कर रही है, उसमें कितने वाहन ई-20 के लिये डिजाइन या प्रमाणित थे। ऐसी किसी बुनियादी जानकारी के बिना, सुरक्षा और परफॉर्मेंस के बारे में दिए गए भरोसे के शब्द शायद ही लोगों को विश्वास दिला पाएं कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उनके लिये लाभकारी है। हाल के दिनों में पूरे देश से इथेनॉल के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। मुद्दा सार्वजनिक विमर्श का विषय बना हुआ है। कुछ संगठन आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के विरोध, विपक्ष की इस मामले में पारदर्शिता की मांग और 'ई-20 जनता पार्टी' जैसे व्यंग्यात्मक ऑनलाइन कैंपेन लोगों की इस बाबत बढ़ती चिंता को ही दर्शाता है। ऐसे में सरकार को इस मुद्दे को समय रहते गंभीरता से लेने की जरूरत है। सही मायने में ग्राहकों को वारंटी सुरक्षा, लंबे समय तक रखरखाव के खर्च, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की माइलेज और इंजन व अन्य उपकरण खराब होने की जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी ही चाहिए। इस बाबत सरकार द्वारा दी गई केवल सफाई भरोसे का आधार नहीं बन सकती। इसके लिये प्रामाणिक तथ्यों की भी जरूरत है। वहीं सरकार के इस बाबत संकेत से कि ज्यादा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाई जा रही है,से यह पता जरूर चलता कि ई-20 आखिरी पड़ाव न हो। निश्चित रूप से इस तरह के किसी कदम के लिये जनता को विश्वास में लेने और डेटा आधारित पॉलिसी बनाने की जरूरत है। किसी नीति के लाभदायक होने के साथ ही जरूरी है लोगों को यह लगना कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

इसरो के लिए प्रतिभाओं को थामे रखने की चुनौती

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अच्छी और बुरी, दोनों वजहों से सुर्खियों में है। अच्छी खबर यह है कि भारत की एक निजी कंपनी, 'स्काईरूट' ने पहला 'एंड-टू-एंड' (आरंभ से अंत तक) निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन पूरा कर दिखाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के दो पूर्व इंजीनियरों द्वारा शुरू की गई इस कंपनी ने अपने रॉकेट, विक्रम-1 की प्रथम उड़ान सफल बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंपनी को उम्मीद है कि वह अगले साल इस रॉकेट का उन्नत प्रारूप विक्रम-2 उड़ा पाएगी। इसका मकसद 'लो अर्थ ऑर्बिट' (पृथ्वी की निचली कक्षा) में सैटेलाइट स्थापित करने के अरबों डॉलर के बाज़ार में उतरना है।

बुरी खबर इसरो के बारे में है, जहां से कई बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक, यू.आर. राव स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और नेशनल स्पेस एजेंसी की अन्य अहम इकाइयों में काम करने वाले दर्जनों वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने या तो इस्तीफ़ा दे दिया है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले ली। इनमें से कई वैज्ञानिक भारत की अग्रणी अंतरिक्ष परियोजनाओं, जैसे कि गगनयान मिशन (इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन), नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (एनजीएलवी) और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों पर काम कर रहे थे।

हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अंतरिक्ष विभाग को इस पलायन पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला करना पड़ा है। उसने निर्देश दिया है कि अहम मिशनों से जुड़े लोगों को परियोजना पूरी होने तक इसरो छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरसरी तौर पर देखें तो भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का प्रक्षेपण और इसरो से प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) एक-दूसरे से अलग लग सकते हैं। लेकिन असल में, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसरो की इकाइयों में इस्तीफ़ों की बाढ़ का सबसे परोक्ष कारण पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनियों का उभरना है। यह सरकार के उस फ़ैसले का सीधा नतीजा है, जिसमें निजी कंपनियों को रॉकेट और सैटेलाइट बनाने तथा उनका प्रक्षेपण करने की इजाज़त दी गई थी। इस नीति के आने से पहले भारतीय भूमि से रॉकेट छोड़ने के काम पर केवल इसरो का

एकाधिकार था। सरकार ने न सिर्फ़ निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाज़े खोल दिए, बल्कि इसरो को यह भी निर्देश दिया कि वह कंपनियों को अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करने दे। इन सबने एक ऐसी स्थिति बना दी, जिसमें निजी कंपनियों ने इसरो की इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को आकर्षक वेतन, सुविधाओं और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं से लुभाकर अपनी ओर खींच लिया।

सरकारी संस्थानों से निजी क्षेत्र में प्रतिभा का इस प्रकार का पलायन इसरो के लिए कोई नई बात नहीं है और न ही यह केवल अंतरिक्ष क्षेत्र तक ही सीमित है। अमेरिका का नामी निजी अंतरिक्ष क्षेत्र, नासा द्वारा तैयार और प्रशिक्षित किए गए लोगों (मानव संसाधन) के दम पर ही खड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आरंभिक दौर में निजी कंपनियों ने अपनी अनुसंधान एवं विकास टीमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों से लोगों को लाकर तैयार की थीं। ऐसा ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) जैसी महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियों के मामले में भी हुआ।

रक्षा एवं एयरोस्पेस उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के बाद, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (डीआरडीओ) की प्रयोगशालाओं में भी इसरो जैसी ही स्थिति बनी हुई है। हमारी वैज्ञानिक एजेंसियों, चाहे वे इसरो हों या डीआरडीओ, को आज जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसके कारणों पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है।

मार्च 2026 में, अंतरिक्ष विभाग की समीक्षा करने वाली एक संसदीय समिति को बताया गया था कि इसरो की अलग-अलग इकाइयों में कुल मंज़ूर 18,000 पदों में लगभग 2,800 से अधिक पद खाली पड़े हैं। नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने वाले संस्थान, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में भी लगभग 500 पद खाली हैं। एक ओर निजी कंपनियां अनुभवी वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींच रही हैं, तो दूसरी तरफ़ इसरो की परियोजनाओं को सरकार से पर्याप्त फंडिंग नहीं मिल रही है।

उदाहरण के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी थी। इसके तहत रॉकेट विकसित करने हेतु, सुविधा शुरू करने से लेकर प्रक्षेपण तक, 96 महीनों की समय-सीमा तय की गई। मंज़ूरी की तारीख से 84 महीनों के भीतर पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मंज़ूरी मिलने के बाद भी कई माह तक यह परियोजना कागज़ों पर ही रही, क्योंकि 2024-25 के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। संशोधित अनुमान के तहत 3 करोड़ रुपये का एक प्रतीकात्मक आवंटन किया गया, जिसमें से इसरो 85 लाख रुपये ही खर्च पाया। 2025-26 के बजट में शुरू में 158 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन संशोधित अनुमानों में इसे भी घटाकर 39.76 करोड़ रुपये कर दिया। इस धन में से इसरो ने 31 जनवरी, 2026 तक केवल 7.93 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए। फंडिंग में देरी और स्टाफ़ की कमी ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की तय समय-सीमा पर बुरा असर डाल सकती है।

फंड का पूरा उपयोग न होना, बजटीय आवंटन में कटौती, खाली पदों को भरने में देरी और निजी क्षेत्र की आमद-ये सभी चीज़ें इसरो में एक गंभीर स्थिति पैदा कर रही हैं। तिस पर, प्रमुख रॉकेट परियोजना यानी पीएसएलवी से जुड़ी कई नाकामियां मिली हैं और गगनयान जैसे मुश्किल मिशनों में भी भारी देरी हुई। निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण तथा बढ़ती अफ़सरशाही एवं सियासी दखलंदाज़ी भी एक बड़े मिशन-उन्मुख वैज्ञानिक संस्थान के कामकाज के लिए अच्छे संकेत नहीं। नतीजन, वैज्ञानिकों का मनोबल गिरा है और वे आमतौर पर निराश महसूस कर रहे हैं।

दिनेश सी शर्मा

यह सब चीज़ें राजनीतिक नेतृत्व, नीति-निर्माताओं और अंतरिक्ष एजेंसी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वैज्ञानिकों से इस्तीफ़ा न देने को कहना और इन्हें स्वीकार न करने का आदेश जारी कर देना ही काफ़ी नहीं। केंद्र सरकार, जिसने निजी क्षेत्र के प्रवेश पर ज़ोर दिया, और इसरो, जिसने इसकी राह आसान की, उन्हें इस राष्ट्रीय कार्यक्रम पर पड़ने वाले इस प्रकार के असर का अंदाज़ा पहले से होना चाहिए था और इससे निबटने को पहले से ही कदम उठाने चाहिए थे। इसरो के नेतृत्व को वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए, जो मिशन की नाकामियों और देरी से प्रभावित हुआ है।

दीर्घकालीन नीति में एजेंसी को नए और अनोखे तरीकों के बारे में सोचना होगा,जैसे कि वैज्ञानिकों को इसरो में अपने कार्य के दौरान ही कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने की इजाज़त देना, गैर-अति महत्वपूर्ण या कम अहम क्षेत्रों में अपनी कंपनियां शुरू करने की अनुमति देना, साथ ही वेतन ढांचा, तरक्की की नीतियों तथा प्रोत्साहनों में बदलाव करना।

अपनी ओर से सरकार को वैज्ञानिक संस्थानों की स्वायत्तता बहाल करनी चाहिए और राजनीतिक फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल बंद करना चाहिए। अंतरिक्ष बाज़ार दुनिया भर में बढ़ रहा है और इस संभावना को तलाशने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों और निजी कंपनियों, दोनों के लिए काफ़ी गुंजाइश है। 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को आसानी से 'ब्रेन सर्कुलेशन' (प्रतिभा आदान-प्रदान) में बदला जा सकता है।

अब राजनीतिक प्राणी बन गया है कॉकरोच

हाल में हुए आंदोलन में कॉकरोच का सम्मान बढ़ गया है। कॉकरोच सदियों से बदनाम प्राणी रहा है। रसोई में दिखे तो चप्पल उठती है, बाथरूम में दिखे तो चीख निकलती है। मगर हाल के आंदोलन ने कॉकरोच की छवि बदल दी। अब कॉकरोच सिर्फ कीड़ा नहीं, राजनीतिक प्रतीक है। कॉकरोच और नेता में बुनियादी समानता यह है कि दोनों को निपटाना आसान नहीं। दोनों का सफाया करो तो नेता अगले चुनाव में फिर उग आता है, कॉकरोच अगली रात फिर रसोई में। दोनों प्रजातियां विलुप्त होने के नाम पर सबसे ज्यादा जीवित रहती हैं। परमाणु युद्ध के बाद भी कॉकरोच बचेगा, यह वैज्ञानिक मानते हैं। सत्ता-परिवर्तन के बाद भी नेता बचेगा, यह जनता मानती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉकरोच को दीवार की दरार चाहिए, नेता को सिर्फ पार्टी बदलने का मौका चाहिए। दोनों दरार खोजने में माहिर हैं।

कॉकरोच अंधेरे में सक्रिय होता है, रोशनी पड़ते ही भाग जाता है। नेता भी रात की बैठकों में सक्रिय होता है, कैमरा आते ही मुस्कुराने लगता है। रोशनी दोनों को पसंद नहीं, हां कैमरे की रोशनी अलग चीज है, वह मंच की रोशनी है, उससे कोई नहीं भागता।

बर्गर एक ऐसी चीज है जो दो परतों के बीच सब कुछ छुपा देती है। ऊपर से देखो तो सिर्फ बन दिखता है, गोल-मटोल, मासूम। अंदर क्या है, यह खाने वाले को भी पक्का पता नहीं चलता। नेता भी ठीक बर्गर जैसा प्राणी है। ऊपर से भाषण की परत, नीचे वादों की परत, बीच में जो असली माल है वह किसी को नहीं दिखता।

बर्गर बहुराष्ट्रीय कंपनी की उपज है, नेता बहुदलीय राजनीति की उपज है। दोनों में असली सामग्री ढूंढना मुश्किल काम है। मेन्यू में लिखा कुछ होता है, प्लेट में मिलता कुछ और है। घोषणापत्र में लिखा कुछ होता है, सरकार में मिलता कुछ और है। बर्गर की कीमत बढ़े तो जनता चुप रहती है, यह सोचकर कि महंगाई है। नेता की कीमत बढ़े यानी चंदा बढ़े तो जनता को पता भी नहीं चलता, यह सोचकर कि लोकतंत्र है।

आलोक पुराणिक

कॉकरोच और नेता, दोनों को हल्के में लेना खतरनाक है। दोनों अनुकूलन के उस्ताद हैं। कीटनाशक बदलो, कॉकरोच नई नस्ल बनाकर लौट आता है। चुनाव चिह्न बदलो, नेता नई पार्टी बनाकर लौट आता है। दोनों को खत्म करने की हर कोशिश उनकी संख्या बढ़ा देती है। कॉकरोच बिना सिर के भी हफ्तों जिंदा रह सकता है, नेता बिना विचारधारा के भी दशकों जिंदा रहता है, बस माइक चाहिए। कॉकरोच को बचने की कला आती है और नेता को भी।

विज्ञान-तकनीक के सहारे सुरक्षित बाघों की दुनिया

हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिन बाघ संरक्षण के साथ प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन के गहरे संबंध का स्मरण भी कराता है। बाघ केवल जंगल का राजा नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रहरी है। जहां बाघ सुरक्षित हैं, वहां जंगल जीवित हैं; जहां जंगल सुरक्षित हैं, वहां नदियां बहती हैं, भूजल संरक्षित रहता है और जैव विविधता फलती-फूलती है। तभी कहा जाता है, 'टाइगर रहेगा तो इंसान भी रहेगा।'

एक समय अवैध शिकार, जंगलों की सिकुड़न, अनियंत्रित शहरीकरण, खनन, सड़क-रेल परियोजनाओं तथा बढ़ते मानव-बाघ संघर्ष ने बाघों की संख्या को चिंताजनक स्तर तक पहुंचा दिया था। वर्ष 2006 में देश में केवल 1,411 बाघ शेष बचे थे। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों, वन विभाग, वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों तथा विभिन्न संस्थाओं ने समन्वित प्रयास शुरू किए। आज विश्व के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में हैं। यह उपलब्धि केवल संरक्षण नीतियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान, तकनीक और जनभागीदारी के सफल प्रयोग का प्रमाण है।

पिछले एक दशक में विज्ञान और तकनीक ने बाघ संरक्षण की तस्वीर बदल दी है। पहले जहां वनकर्मियों को कई दिनों तक जंगलों में पैदल घूमकर पगचिह्नों के आधार पर अनुमान लगाना पड़ता था, वहीं आज कैमरा ट्रैप, एआई, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी, जीपीएस कॉलर और डिजिटल डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों ने संरक्षण कार्य को अधिक सटीक, पारदर्शी और प्रभावी बना दिया है। कैमरा ट्रैप आज बाघ संरक्षण का सबसे विश्वसनीय उपकरण माना जाता है। ये विशेष कैमरे मोशन सेंसर की सहायता से किसी भी वन्यजीव की तस्वीर या वीडियो स्वतः रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाघों की पहचान उनके शरीर पर बनी धारियों से होती है और प्रत्येक बाघ की धारियां मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह अलग होती हैं। कैमरा ट्रैप से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिक प्रत्येक बाघ की अलग पहचान कर उसकी गतिविधियों, क्षेत्र, प्रजनन और संख्या का सटीक आकलन कर पाते हैं। यही कारण है कि भारतीय बाघ गणना आज दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक वन्यजीव निगरानी परियोजनाओं में गिनी जाती है।

दरअसल, कैमरा ट्रैप से हर वर्ष लाखों तस्वीरें और वीडियो प्राप्त होते हैं। पहले इनका विश्लेषण करने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब एआई आधारित सॉफ्टवेयर कुछ ही घंटों में यह पहचान लेते हैं कि तस्वीर में बाघ है, तेंदुआ है, हाथी है या कोई अन्य वन्यजीव। इतना ही नहीं, एआई बाघों की धारियों का विश्लेषण करके उनकी व्यक्तिगत पहचान भी सुनिश्चित कर सकता है। इससे गणना अधिक सटीक हुई है और समय की उल्लेखनीय बचत हुई है।

मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां बाघों की गतिविधियों का विश्लेषण कर यह बताने में सक्षम हैं कि किसी क्षेत्र में मानव-बाघ संघर्ष की आशंका कितनी है, किस दिशा में बाघों का आवागमन बढ़ रहा है और किन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार एआई भविष्य की संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। घने जंगलों में ड्रोन तकनीक उपयोगी सिद्ध हुई है। आधुनिक ड्रोन उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों और थर्मल इमेजिंग सिस्टम से लैस होते हैं, जिससे वे रात के समय भी जंगलों की निगरानी कर सकते हैं। इनके माध्यम से अवैध शिकार करने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और जंगलों में आग लगने की प्रारंभिक जानकारी मिल सकती है। इससे दुर्गम क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है।

वहीं, अंतरिक्ष से प्राप्त चित्रों के आधार पर जंगलों में हो रहे परिवर्तनों की लगातार निगरानी की जाती है। यदि कहीं अवैध कटाई, अतिक्रमण या वन क्षेत्र में कमी दिखाई देती है तो संबंधित एजेंसियां तत्काल कार्रवाई कर सकती हैं। इससे बाघों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने में सहायता मिल रही है।

आज अधिकांश टाइगर रिजर्व में वनकर्मी जीपीएस आधारित मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से गश्त करते हैं। उनकी गतिविधियां डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होती हैं। किस क्षेत्र में कितनी गश्त हुई, कहां वन्यजीव दिखाई दिए, कहां संदिग्ध गतिविधियां मिलीं–सारी जानकारी तुरंत नियंत्रण कक्ष तक पहुंच जाती है। डिजिटल डेटा के विश्लेषण से सुरक्षा रणनीति तैयार की जाती है। कुछ बाघों को विशेष जीपीएस रेडियो कॉलर भी पहनाए जाते हैं। इनके माध्यम से वैज्ञानिक उनकी लोकेशन, आवागमन, प्रजनन क्षेत्र और भोजन की तलाश से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई बाघ मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहा हो तो वन विभाग पहले से सतर्क होकर जरूरी कदम उठा सकता है। भोजन या नए क्षेत्र की तलाश में कभी-कभी बाघ गांवों तक पहुंच जाते हैं, जिससे मानव-बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं। अब एआई आधारित चेतावनी प्रणाली से संबंधित गांवों और वन अधिकारियों को तुरंत सूचना भेजी जाती है। इससे ग्रामीण सतर्क हो जाते हैं।

डॉ. सुशील द्विवेदी

बाघों के सामने आज सबसे बड़ा खतरा अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी है। अब एआई संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण करता है, ड्रोन जंगलों की निगरानी करते हैं और कैमरा ट्रैप संदिग्ध गतिविधियों की तस्वीरें रिकॉर्ड करते हैं। वहीं, डिजिटल नेटवर्किंग से वन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से दुनिया में संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की है।

सीएम हाउस तक कूच की तैयारी में किसान

भोपाल।

मध्य प्रदेश में मूंग की 100 फीसदी एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च कर पहुंचे किसानों ने राजधानी के सावरकर सेतु के पास डेरा डाल रखा है। इस बीच राज्य सरकार ने भी केंद्र से हस्तक्षेप की मांग करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। वहीं किसान अब मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने की तैयारी में हैं।

भोपाल में एमएसपी को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच एसीपी आदित्य राज सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ स्तर पर बातचीत जारी है और आगे की कार्रवाई अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

भोपाल में प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने कहा कि किसान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि वे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हर स्तर पर रोकने की कोशिश की और आगे बढ़ने से रोककर उनके साथ अन्याय किया। किसान ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में मूंग की 100 फीसदी खरीद और ई-टोकन व्यवस्था को खत्म करना शामिल है।

भोपाल में प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने कहा कि उनकी मांग है कि मूंग की 100 फीसदी फसल की खरीद की जाए और ई-टोकन व्यवस्था को या तो सही तरीके से लागू किया जाए या फिर पूरी तरह खत्म किया जाए। किसान ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक वे भोपाल में ही डटे रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद कर रही है कि किसान कोई गड़बड़ी करें ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। किसान ने कहा कि उनका सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या किसी प्रशासनिक अधिकारी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की कि उन्हें हर कदम पर न रोका जाए, क्योंकि वे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी में बताया है कि राज्य में 14 मई से 3 जुलाई 2026 के बीच करीब 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है, जबकि फिलहाल 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। उनका कहना है कि मौजूदा लक्ष्य के कारण बड़ी संख्या में किसान एमएसपी का लाभ नहीं ले पाएंगे।

करीब 2,000 किसान अनाज की बोरियां, बिस्तर, खाना बनाने के बर्तन और एक सप्ताह तक चलने वाला राशन लेकर भोपाल पहुंच चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दर्जनों किसान संगठनों का यह मार्च पुलिस की कई बैरिकेडिंग पार करते हुए राजधानी के बाहरी इलाके तक पहुंचा। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक मूंग की 100 फीसदी एमएसपी पर खरीद और खाद वितरण से जुड़ी उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक वे भोपाल से वापस नहीं लौटेंगे।

बैरिकेडिंग के बावजूद आगे बढ़े किसान

मंगलवार रात किसान भोपाल के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। राजधानी में किसानों की मौजूदगी के साथ यह आंदोलन मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के सामने इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक बनता नजर आ रहा है।

चिट्ठी में और क्या कहा गया?

कृषि मंत्री ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इस साल औसत उत्पादकता बढ़ने से मूंग का उत्पादन अनुमान से अधिक हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 4.19 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीद हो चुकी है और मौजूदा रफ्तार को देखते हुए तय लक्ष्य जल्द पूरा होने की संभावना है।

प्रदेश का देश के उत्पादन में 40 प्रतिशत हिस्सा

चिट्ठी में कृषि मंत्री ने यह भी जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश देश के कुल मूंग उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। ऐसे में किसानों के हितों को देखते हुए केंद्र सरकार को खरीद सीमा बढ़ाने पर विशेष निर्णय लेना चाहिए। गौरतलब है कि बीती रात राज्य कृषि मंत्री और किसानों के बीच एक घंटे बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही थी।

किसानों से मिले कृषि मंत्री

इससे पहले मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि मूंग खरीदी समेत सभी मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

किसानों की प्रमुख मांगें

संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में मूंग की 100 फीसदी एमएसपी पर खरीद, ई-टोकन व्यवस्था की समस्याओं का समाधान और समय पर उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना शामिल है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

नागदा-गोधरा रेलखंड पर 302 किमी में लगा कवच सिस्टम

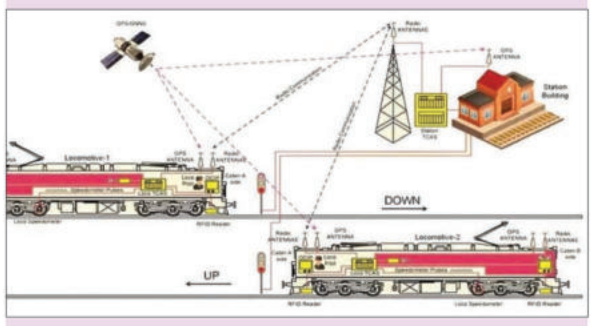

माही की गूंज, रतलाम।

यात्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नागदा-गोधरा रेलखंड पर स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) सिस्टम कवच का कार्य पूरी तरह पूरा हो गया है।

रतलाम मंडल में 20 जुलाई को पंचपिपलिया-मंगल महुड़ी के लगभग 78 रूट किलोमीटर रेलखंड पर कवच प्रणाली की सफल कमीशनिंग के साथ ही नागदा-गोधरा रेलखंड के संपूर्ण 302 रूट किलोमीटर मार्ग पर यह अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह कार्यशील हो गई है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि इससे पहले 30 मार्च को प्रथम चरण में 224 रूट किलोमीटर रेलखंड पर कवच प्रणाली लागू की गई थी। शेष 78 रूट किलोमीटर पर सफल कमीशनिंग के बाद अब दिल्ली-मुंबई उच्च घनत्व रेल मार्ग पर रतलाम मंडल का पूरा नागदा-गोधरा रेलखंड इस सुरक्षा प्रणाली से लैस हो गया है

डीआरएम अश्विनी कुमार ने बताया कि दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग देश के सबसे व्यस्त और उच्च घनत्व वाले रेल मार्गों में शामिल है। ऐसे महत्वपूर्ण रेलखंड पर कवच का सफल क्रियान्वयन सभी विभागों के समन्वय, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क का परिणाम है।

मिशन रफ्तार का हिस्सा

यह परियोजना रेलवे के मिशन रफ्तार का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पूरे मार्ग पर ब्रिजों की मरम्मत, ओएचई रखरखाव, सिग्नलिंग सिस्टम का उन्नयन, कर्व री-अलाइनमेंट और एच-बीम स्लीपर लगाने जैसे कार्य भी किए गए।

आमने-सामने आने पर ट्रेन में स्वतः लग जाएगा ब्रेक

कवच रेलवे की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे आरडीएसओ ने विकसित किया है। इंजन में लगे सेंसर, जीपीएस और रेडियो संचार प्रणाली के माध्यम से यदि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने-सामने आ जाएं या चालक लाल सिग्नल पार करने का प्रयास करे, तो यह प्रणाली स्वतः ब्रेक लगा देती है।

साथ ही यह ओवरस्पीड रोकने, लोको पायलट को रियल टाइम सिग्नल जानकारी देने, पीछे से होने वाली टक्करों को रोकने, गति प्रतिबंधों का पालन कराने, लेवल क्रासिंग पर चेतावनी देने और आपात स्थिति में एसओएस संदेश भेजने में भी सक्षम है। इससे ट्रेन परिचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

शादी के 27 दिन बाद पति ने सुनाई दर्द भरी दास्तां

माही की गूंज, शाजापुर।

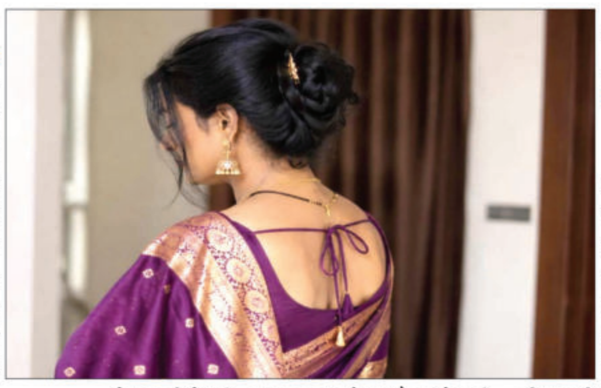

जिले से अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी थर्ड जेंडर (किन्नर) से कराई गई। शादी के तुरंत बाद जानकारी नहीं मिली। एक महीने बाद इस बात का खुलासा हुआ। मामला सामने आने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना हुई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दुल्हन को तुरंत ले जाने की करी जिद्द

शाजापुर निवासी युवक का विवाह 29 जून 2026 को राजगढ़ जिले के पचोर स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी के एक महीने बाद उन्हें पता चला कि दुल्हन थर्ड जेंडर है, जिसके बाद दोनों पक्षों में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष और मारपीट में बदल गया। युवक ने शुक्रवार को थाने में शिकायत की। इसके अनुसार शुक्रवार रात करीब 10 बजे पचोर से लड़की के परिजन आजाद, राकेश और चंदो बाई घर पहुंचे और दुल्हन को तुरंत ले जाने की जिद्द करने लगे। जब युवक ने सुबह जाने की बात कही तो आरोपियों ने गाली-गलौज और झूमाझटकी शुरू कर दी।

शोर सुनकर जब युवक के भाई और भाभी बीच-बचाव करने आए तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लकड़ी से वार कर भाभी के दोनों हाथों को चोट पहुंचाई और दांत से काट लिया। सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर भाई की उंगली को जख्मी कर दिया।

शादी के नाम पर 1 लाख लेने का आरोप

पीड़ित के भाई का कहना है कि उन्होंने शादी के लिए लड़की के परिजनों को एक लाख रुपए भी दिए थे। शादी के बाद जब दुल्हन की सच्चाई सामने आई तो बातचीत के जरिए मामला सुलझाने के लिए परिजनों को बुलाया गया था, लेकिन वे हिंसा और मारपीट पर उतर आए। जाते-जाते आरोपी जान से मारने की धमकी भी दे गए।

पांच लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज

कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी आजाद, राकेश, राजा, चंद्रोबाई और लक्ष्मीनारायण सभी निवासी पचोर, जिला राजगढ़ के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है।

कटौती से आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्रिड पर की तोड़फोड़

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में दो दिन से रात में कटौती की जा रही है। रविवार के सोमवार को भी रात 8 बजे से कटौती की गई। ग्राम रेवास-देवड़ा में आक्रोशित ग्रामीण ग्रीड पर जा पहुंचे। वहा हंगामा किया और खिड़कियों के कांच भी तोड़े। कटौती को लेकर ग्रामीणों ने काफी देर तक ग्रीड का घेराव भी करके रखा। बाद में मौके पर डायल112 पहुंची। उल्लेखनीय है कि मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लोड मैनेजमेंट के नाम पर रविवार रात में भी 10 बजे से 11 बजे तक कटौती की थी।

इसके बाद सोमवार को रात 8 बजे से ही कटौती शुरू कर दी। ग्रामीणों में इसी बात का गुस्सा है कि अब लोड शेडिंग के नाम पर सभी को परेशान किया जा रहा है। रात में बाजार बंद हो चुके होते हैं, गलियां अंधेरी रहती हैं। ऐसे समय में बिजली बंद होने से घरों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

विद्युत कंपनी की यह मनमानी भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 24 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन है।

उपभोक्ताओं को समय पर और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति देना कंपनी की जिम्मेदारी है। बिना पर्याप्त सूचना और जनहित को ध्यान में रखे कटौती करना सेवा में कमी है। लोगों का कहना है क्ययदि लोड मैनेजमेंट के नाम पर रात में अंधेरा करके कोई चोरी या हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार क्या विद्युत मंडल के अधिकारी-कर्मचारी होंगे?

कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई

माही की गूंज, शाजापुर।

शहर के काशीनगर में ट्रेडिंग एडवाइजरी काल सेंटर पर दबिश देकर लालघाटी थाना पुलिस ने सात युवकों को पकड़ा है। इस दौरान सेंटर संचालित करने वाला सरगना भाग निकला। पुलिस को यहां से साइबर ठगी किए जाने की आशंका है। हिरासत में लिए गए युवकों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे उपलब्ध कराई सूची में दर्ज मोबाइल नंबरों पर कॉल करते थे।

सिर्फ ट्रेडिंग में रुचि होने या न होने की बात कन्फर्म करते थे। इसके लिए इच्छुक लोगों के नंबर सेंटर संचलक प्रवीण गोयल को दे देते थे। पुलिस ने युवकों के मोबाइल व अन्य रिकार्ड जब्त कर इस्तगासा दर्ज किया है। बताया कि साइबर सेल की टीम मामले की जांच कर रही है।

बॉयफ्रेंड को आ गया गुस्सा... गला घोंटा

इंदौर।

कमरे के अंदर धुआं था। चारों तरफ जले हुए सामान के निशान थे। बीच में एक अधजला शव पड़ा था। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे गैस रिसाव हुआ हो... या शायद युवती ने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई... और रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी।

यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना इलाके का है। 26 जुलाई को तपेश्वरी बाग कॉलोनी में किराए के मकान से बैंक में काम करने वाली युवती पलक काशिव का अधजला शव मिला था।

पलक पिछले दो दिनों से अपने परिवार के संपर्क में नहीं थीं। कमरे का सीन देखकर शुरुआत में हादसे या आत्महत्या की आशंका जताई गई थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि पलक की मौत आग से नहीं हुई थी। पुलिस के मुताबिक, उनकी मौत पहले ही गला दबाने से हो चुकी थी। यानी आग बाद में लगाई गई थी।

यहीं से जांच की दिशा बदल गई। खजराना थाना पुलिस ने एफएसएल की मदद से घटनास्थल से सबूत जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसी दौरान एक फुटेज सामने आई, जिसमें एक युवक पेट्रोल का डिब्बा लेकर घटनास्थल की ओर जाता दिखाई दिया। यही पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग बना।

तकनीकी सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। उसकी पहचान ग्वालियर जिले के डबरा निवासी मयंक शाक्य के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि वह पिछले करीब पांच साल से पलक का करीबी दोस्त था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था।

पुलिस का कहना है कि जब पलक ने शादी से इनकार किया, तो गुस्से में आकर आरोपी ने कथित तौर पर उसका गला दबा दिया। इसके बाद शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और कमरे में ऐसा माहौल बनाया कि मामला हादसा या आत्महत्या लगे। इंदौर पुलिस के मुताबिक, आरोपी का मकसद हत्या के सबूत मिटाना और जांच को दूसरी दिशा में मोड़ना था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी कथित साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने आरोपी मयंक को गिरफ्तार कर हत्या और साक्ष्य नष्ट करने सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या की प्लानिंग पहले से बनाई गई थी या नहीं और क्या इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका थी।

46 वर्ष बाद गायत्री शक्तिपीठ में हुई प्राण-प्रतिष्ठा, 10 हजार श्रद्धालु बने साक्षी

माही की गूंज, खरगोन।

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शहर के गायत्री शक्तिपीठ में बुधवार को 46 वर्षों के इंतजार के बाद ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। शक्तिपीठ में युगऋषि पं. राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा के प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा स्वरूपों की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण-प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर देशभर से आए श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूरा परिसर भक्ति और श्रद्धा के वातावरण से सराबोर रहा।

प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की विशेषता यह रही कि स्वरूपों के नीचे श्रद्धालुओं द्वारा लिखी गई 24 करोड़ गायत्री मंत्रों की हस्तलिखित पुस्तिकाएं स्थापित की गईं। इसके साथ ही देश के 24 प्रमुख तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल और रज (मिट्टी) को भी विधि-विधान के साथ प्रतिष्ठित किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत 24 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन भी हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित कर विश्व शांति, मानव कल्याण और राष्ट्र निर्माण की कामना की। पूरे दिन शक्तिपीठ परिसर में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा।

सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। दोपहर तक 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 1,500 से अधिक लोगों ने गुरुदीक्षा ग्रहण कर समाज जागरण, संस्कार निर्माण, नशामुक्ति, परिवार निर्माण और राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया।

गायत्री परिवार के परिव्राजक सौरभ मोरे ने बताया कि प्राण-प्रतिष्ठा से पूर्व देश के 24 प्रमुख तीर्थों से पवित्र जल और रज एकत्रित की गई थी। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा वर्षों की साधना से लिखी गई 24 करोड़ गायत्री मंत्रों की पुस्तिकाओं को भी स्वरूपों के नीचे स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, संस्कारों और युग निर्माण के संदेश को सशक्त बनाने का माध्यम भी है। गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना के 46 वर्ष बाद हुई यह प्राण-प्रतिष्ठा संस्था के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है।

धूनीवाले दादाजी मंदिर का होगा पुनर्निर्माण, वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य

माही की गूंज, खंडवा।

प्रसिद्ध धूनीवाले दादाजी मंदिर को जल्द ही नया और भव्य स्वरूप मिलने जा रहा है। दादा धूनीवाले के समाधिस्थ होने के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले वर्ष 2030 तक मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर की नींव रखी जा चुकी है।

नए मंदिर का निर्माण चार चरणों में किया जाएगा। पूरे मंदिर में सफेद संगमरमर का उपयोग होगा, जिससे दादा दरबार का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। मंदिर की रूपरेखा अक्षरधाम मंदिर के वास्तुकार वीरेंद्र त्रिवेदी तैयार कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर का चयन किया जा रहा है और इसके नमूने भी खंडवा पहुंच चुके हैं।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए मंदिर में दो के स्थान पर तीन प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इसके अलावा करीब 23 एकड़ में फैले आश्रम परिसर का भी विकास किया जाएगा। भक्त निवास, गोशाला, उद्यान, प्रसादालय और अन्य सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंदिर निर्माण को लेकर पिछले कुछ वर्षों से विवाद बना हुआ था। सभी पक्षों की सहमति बनने के बाद अब निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मंदिर निर्माण समिति के पदेन सदस्य एवं कलेक्टर ऋषव गुप्ता के अनुसार वर्ष 2030 तक इस भव्य मंदिर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

चैराहे पर निगरानी हेतु कैमरे लगाने की मांग

माही की गूंज, बड़वानी।

शहर के मायरिया चैराहा और पानवाड़ी मोहल्ले के रहवासियों ने क्षेत्र में कथित असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी कैमरे लगाने की मांग की है। इस संबंध में मोहल्लेवासियों ने शहर कोतवाली थाना पहुंचकर पुलिस प्रशासन को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा।

रहवासियों कृष्णा गोले, कालू मायरिया सहित अन्य लोगों ने ज्ञापन में बताया कि पिछले कुछ समय से मायरिया चैराहे पर कुछ युवकों का जमावड़ा लगा रहता है। उनका आरोप है कि यहां हुड़दंग, विवाद और सार्वजनिक स्थान पर नशा करने जैसी गतिविधियां होती हैं।

मोहल्लेवासियों के अनुसार रात करीब 1 से 2 बजे के बीच कुछ युवक शराब का सेवन कर आपस में गाली-गलौज और विवाद करते हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों में असुरक्षा का माहौल बना रहता है। उनका कहना है कि विवाद से बचने के लिए लोग ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखते हैं।

रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि चैराहे से गुजरने वाली महिलाओं और बच्चों पर कुछ युवक फब्तियां कसते हैं। उनका कहना है कि इससे कई बार विवाद की स्थिति बनती है तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है।

ज्ञापन में बताया गया कि मायरिया चैराहे और आसपास के घरों में निगरानी कैमरे नहीं लगे हैं। रहवासियों के अनुसार कैमरे नहीं होने से चैराहे पर होने वाली गतिविधियों का अभिलेखन नहीं हो पाता। उनका मानना है कि निगरानी कैमरे लगने से पुलिस को क्षेत्र पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

मोहल्लेवासियों ने पुलिस प्रशासन से मायरिया चैराहे पर शीघ्र निगरानी कैमरे लगवाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र की निगरानी बेहतर होगी और रहवासियों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।

गुरु पूर्णिमा पर मंत्री टेटवाल ने किया पौधारोपण

माही की गूंज, बड़वानी।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री एवं कौशल विकास तथा रोजगार राज्य मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल ने अंजड़ नगर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने सरस्वती मंदिर की पहाड़ी पर चरणबद्ध तरीके से 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया।

डॉ. टेटवाल बुधवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मंदिर में पूजन-अर्चन के साथ हुई।

पौधारोपण के दौरान मंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। इनसे स्वच्छ वायु, फल, फूल तथा औषधियां प्राप्त होती हैं। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह अभियान गुरुजनों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से अपने जन्मदिन और त्योहारों पर कम से कम एक पौधा लगाने का आह्वान किया।

अभियान में नगरवासियों, मातृशक्ति और युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, मंडल अध्यक्ष ऋतुराज चैहान, पूर्व विधायक चंद्रभागा किराडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पौधारोपण अभियान सफल और प्रभावी बन सके।

29.83 करोड़ रुपए की लागत से बने तीन सांदीपनी विद्यालय भवनों का लोकार्पण

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले में 29.83 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तीन सांदीपनी विद्यालय भवनों का बुधवार को लोकार्पण किया गया। सेंधवा विकासखंड के पहले सांदीपनी विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य ने किया।

समारोह के दौरान सेंधवा के साथ पानसेमल के दौदवाड़ा तथा बड़वानी के तलवाड़ा बुजुर्ग स्थित सांदीपनी विद्यालय भवनों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

नवनिर्मित विद्यालय भवनों में स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, खेल सुविधाएं तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। प्रभारी मंत्री डॉ. टेटवाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विज्ञान एवं चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन किया।

डेंगू वैक्सीन को मंजूरी से आगे की राह

एक समय था जब मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली वह बीमारी थी जिससे ज़्यादातर भारतीय डरते थे। इसके विपरीत डेंगू को कम प्रचलित और कम खतरनाक माना जाता था। वह स्थिति अब नाटकीय रूप से उलट गई। पिछले दो दशकों में, डेंगू भारत और दूसरी जगहों पर तेज़ी से फैला। अब यह बुखार होने, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आने और मौत तक का जाना-पहचाना कारण है, खासकर मॉनसून में और उसके बाद। फिर भी, मलेरिया के उलट - जिसके लिए असरदार दवाएं हैं - डेंगू का कोई खास एंटीवायरल इलाज नहीं है।

डेंगू की वैक्सीन विकसित करना मुश्किल साबित हुआ है। कई वैक्सीन आईं, लेकिन हरेक के साथ वैज्ञानिक, सुरक्षा या क्रियान्वयन की चुनौतियां रहीं। इस परिदृश्य में, भारत के दवा नियामक संस्थान द्वारा टाकेडा संस्थान की डेंगू वैक्सीन, %क्यूडेंगा% को मंज़ूरी देना स्वागत योग्य कदम है। भारत को एक ऐसी बीमारी के खिलाफ़ एक अन्य हथियार की ज़रूरत है, जो अब सिर्फ़ मौसमी नहीं रही। डेंगू तेज़ी से शहरी इलाकों में फैल रहा है, बार-बार हो रहा है और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हालांकि, इस मंज़ूरी को जनस्वास्थ्य की सफलता नहीं समझना चाहिए। कोई वैक्सीन असरदार हो सकती है, लेकिन अगर वह महंगी हो, सही लोगों तक न पहुंचे या आसानी से उपलब्ध न हो, तो उसका असर सीमित हो सकता है। बाजार में उतारने की मंज़ूरी मिलने के बावजूद, यह वैक्सीन देश में अगले छह माह तक उपलब्ध नहीं। पहली खेप 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है।

अनुमान है कि डेंगू के कुल वैश्विक मामलों में लगभग एक-तिहाई भारत में होते हैं। पिछले दो दशकों में दर्ज किए गए संक्रमणों की संख्या ग्यारह गुणा से ज़्यादा बढ़ गई है। आधिकारिक तौर पर, भारत में 2025 में लगभग 1.2 लाख मामले और 131 मौतें दर्ज की गईं। ये आंकड़े बीमारी के असल बोझ को कम दिखाते हैं। कई संक्रमणों की जांच नहीं होती, कई मरीज़ों का इलाज दर्ज नहीं होता है, और कुछ मौतों की वजह आघात,रक्त स्राव जैसी जटिलताएं मान ली जाती हैं। 2026 के निगरानी आंकड़े पहले ही बताते हैं कि मुख्य मॉनसून सीज़न शुरू होने से पूर्व ही प्रसार बढ़ने लगा है।

डेंगू वैक्सीन का इतिहास बताता है कि सावधानी क्यों ज़रूरी है। सनोफ़ी संस्थान द्वारा विकसित %डेंगवैक्सिया% को शुरू में बड़ी कामयाबी माना गया था। बाद में पता चला कि जिन लोगों को कभी डेंगू नहीं हुआ था, उन्हें वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित होने पर बीमारी बिगड़ जाने का खतरा ज्यादा बन सकता है। इस स्थिति को %एंटीबॉडी-डिपेंडेंट एन्हांसमेंट% कहा जाता है। इस वजह से वैक्सीन लगाने से पहले जांच ज़रूरी हो गई और इसे लागू करना मुश्किल। फ़िलीपींस में हुए विवाद ने भरोसा कम कर दिया। सबक यह नहीं कि डेंगू वैक्सीन खारिज कर दी जाए, बल्कि यह कि डेंगू की जैविकी जटिल है और सबूतों से पूर्व उत्साह नहीं बनाना चाहिए।

क्युडेंगा लेकिन अलग है। यह एक टेट्रावेलेंट लाइव-एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो कमजोर डीईएनवी-2 बैकबोन पर आधारित है, जिसमें अन्य तीन डेंगू सीरोटाइप का जेनेटिक मैटीरियल शामिल है। भारत ने इसे चार से साठ साल की उम्र के लोगों के लिए मंज़ूरी दी है। तीन महीने के अंतराल पर दो डोज़ में दी जाती है, जिसमें यह सत्यापन करने की जरूरत नहीं कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ है या नहीं। परीक्षणों में डेंगू के सत्यापित मामलों में एक साल में इसकी प्रभावशीलता करीब 80 फीसदी रही और कुछ विश्लेषणों में, 18 महीने में अस्पताल में भर्ती होने की नौबत के मामलों में 90 प्रतिशत से ज़्यादा की कमी आई।

ये आंकड़े उत्साहजनक हैं, लेकिन इन्हें सावधानी से समझने की ज़रूरत है। तमाम संक्रमणों की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने से बचाव होता ज़्यादा मज़बूत दिखाई देता है, जो एक बड़ा फायदा है। हालांकि, समय के साथ असर कम हो जाता है, और कुछ आबादी में डीईएनवी-3 और डीईएनवी-4 के लिए सबूत कमज़ोर या कम निश्चित रहे हैं। भारत में बाजार में इसकी उपलब्धता के बाद अलग-अलग उम्र के लोगों, इलाकों और फैल रहे सीरोटाइप के बीच निगरानी, पारदर्शी सूचना और स्थानीय स्टडीज की ज़रूरत होगी।

क्यूडेंगा को 40 से अधिक देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व योग्यता और अनुमोदन प्राप्त हुआ है। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल-ई के साथ हुई टाकेडा की साझेदारी से भारत में सालाना 5 करोड़ खुराक तक की उत्पादन क्षमता बनने की उम्मीद है, जो 2030 तक प्रति वर्ष 10 करोड़ खुराक के वैश्विक लक्ष्य में योगदान देगा। यह भारत को एक मुख्य उत्पादन केंद्र बना सकता है।

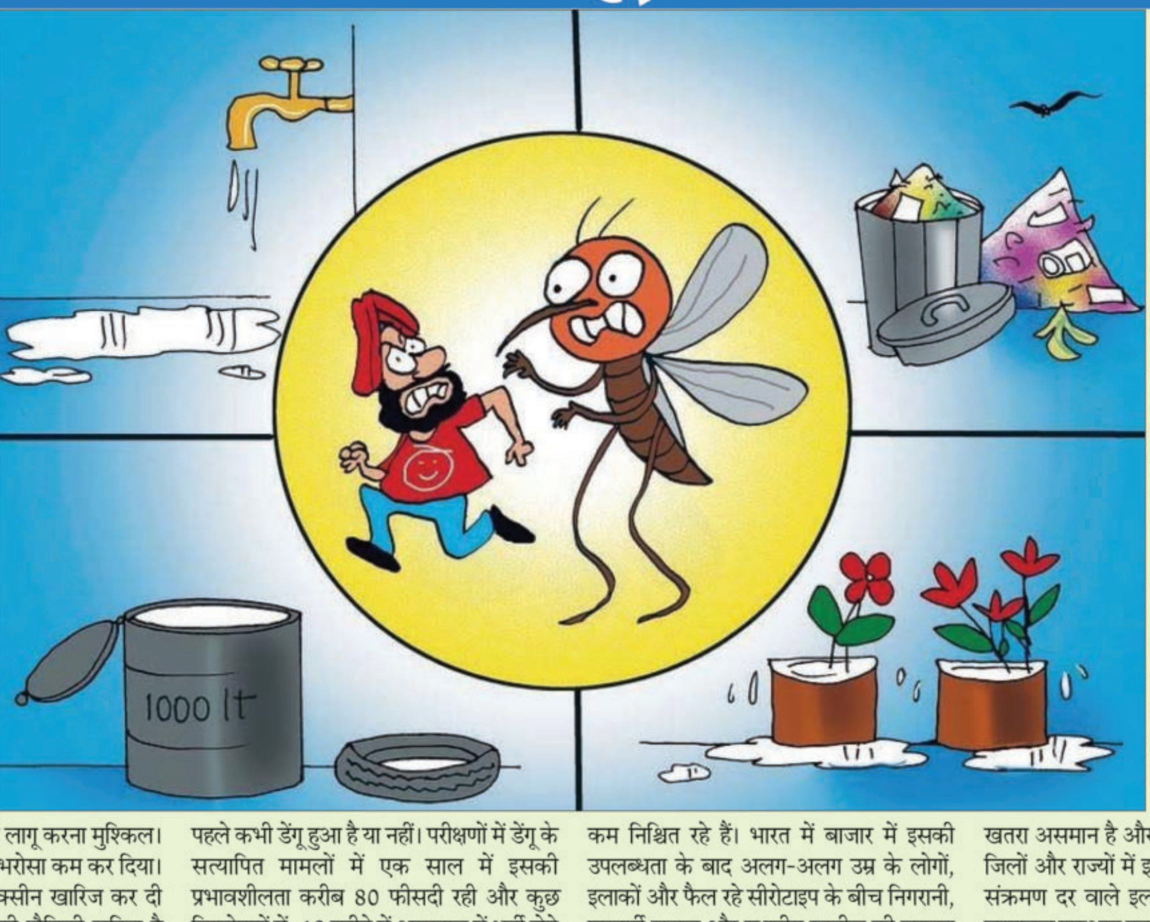

फिर भी मंज़ूरी तो केवल शुरुआत है। किसी गोदाम, निजी क्लिनिक या सरकारी अधिसूचना में रखी वैक्सीन तब तक किसी बीमारी को नहीं रोकती जब तक यह जरूरतमंद लोगों तक न पहुंच पाए। मूल्य संबंधी सौदेबाज़ी, खरीद, कोल्ड-चेन व्यवस्था, स्वास्थ्य-कार्यकर्ता प्रशिक्षण, सार्वजनिक संचार और सरकारी योजना तय करेगी कि क्यूडेंगा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कवच बन जाएगी या नहीं।

देश को यह तय करना होगा कि वैक्सीन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम न तो किफायती हो सकता है और न ही महामारी की परिभाषा के हिसाब से एक आवश्यकता है। डेंगू का खतरा असमान है और अक्सर कुछ खास शहरों, जिलों और राज्यों में इसका प्रकोप होता है। उच्च संक्रमण दर वाले इलाकों में निगरानी आधारित चरणबद्ध शुरुआत करना समझदारी होगी। सरकार को अधिक जोखिम वाली आबादी के लिए सार्वजनिक खरीद पर विचार करना चाहिए, सार्वजनिक एवं निजी उपयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाले मूल्य के निर्धारण पर बात करनी होगी और किफायती दाम पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घरेलू विनिर्माण का उपयोग करना होगा।

टीकाकरण के साथ-साथ निगरानी में भी सुधार होना चाहिए। इस काम में भारत को बेहतर जिला-स्तरीय डेटा, निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से पूरी रिपोर्टिंग और डेंगू सीरोटाइप के फैलाव पर जानकारी की आवश्यकता होगी। वहीं देश भर में कम मात्रा में दवा वितरित करने के बजाय अधिक संक्रमण वाले इलाकों में सीमित मात्रा में खुराक को केंद्रित करने से अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

डॉ. चंद्रकांत लहरिया

टीकाकरण कमजोर मच्छर नियंत्रण का बहाना नहीं बनना चाहिए। डेंगू की रोकथाम प्रजनन स्थलों को खत्म करना, रुके हुए पानी को साफ करना, जल निकासी में सुधार, लारवा-उन्मूलक का उपयोग और रस्मी फॉगिंग की बजाय रणनीति बनाकर किए गए धुंआकरण पर निर्भर रहेगी। नागरिकों को मच्छर-भगाऊ क्रीम, जाली, मच्छरदानी और मच्छरों के डंक से बचाने वाले कपड़ों का उपयोग करना जारी रखना होगा। शीघ्र निदान और निगरानी आवश्यक है।

लोगों की भी भूमिका भी अहम है। उपलब्धता, मूल्य निर्धारण और बाधाएं हल होने के बाद, तय आयु वर्ग के लोग योग्य डॉक्टरों की टीकाकरण पर सलाह ले सकते हैं। जो लोग निजी पहुंच का खर्च वहन करने में सक्षम हैं, उन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं। लेकिन टीकाकरण को बतौर सुरक्षा परत देखा जाए, न कि घर में कूलर, बर्तन या नाली में थमा पानी अनदेखा करने की अनुमति के रूप में।

क्यूडेंगा के रूप में डेंगू के खिलाफ देश को उपयोगी हथियार मिल गया है। क्या यह लाखों लोगों के लिए सार्थक सुरक्षा कवच बन पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तालियां ख़त्म होने के बाद क्या किया जाता है।

सावन के हर सोमवार पर उज्जैन के स्कूल रहेंगे बंद

माही की गूंज, उज्जैन।

सावन के महीने में भगवान श्री महाकालेश्वर की साप्ताहिक सवारी के दौरान शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उज्जैन जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए सवारी वाले प्रत्येक सोमवार को शहर के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। इसके बदले रविवार को नियमित रूप से स्कूल संचालित किए जाएंगे।

श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लिया गया निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने बताया कि सावन के हर सोमवार बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। इसी दिन शाम को भगवान महाकाल की भव्य सवारी भी निकलती है, जिससे शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ और यातायात का दबाव रहता है। विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

रविवार को होगी नियमित पढ़ाई

शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सावन और भादौ महीने में सवारी वाले प्रत्येक सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे, जबकि उनकी भरपाई रविवार को नियमित कक्षाएं लगाकर की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और शैक्षणिक कार्य भी समय पर पूरा किया जा सकेगा।

विद्यार्थियों को मिलेगा महाकाल की सवारी में शामिल होने का अवसर

प्रशासन का मानना है कि सोमवार को अवकाश रहने से विद्यार्थी और उनके परिजन बिना किसी परेशानी के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे और पारंपरिक सवारी में भी शामिल हो पाएंगे। इससे धार्मिक आयोजन के दौरान यातायात का दबाव भी कम होगा और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सुविधा मिलेगी।

यह रहेगा महाकाल की सवारी का मार्ग

भगवान महाकाल की सवारी शाम 4 बजे महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पूजन के बाद शुरू होगी। इसके बाद सवारी महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार, कहारवाड़ी, रामघाट, रामानुजकोट, कार्तिक चौक, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार होते हुए वापस महाकाल मंदिर पहुंचेगी। रामघाट पर विशेष पूजन-अर्चन भी किया जाएगा।

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नई व्यवस्था का पालन करें और स्कूलों द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार बच्चों को रविवार को विद्यालय भेजें। यह व्यवस्था सावन-भादौ महीने में भगवान महाकाल की साप्ताहिक सवारियों की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कार्यक्रम आयोजित

माही की गूंज, उदयगढ़। खलील मंसूरी

जिले की ग्राम पंचायत उदयगढ़ में जिला पंचायत सीईओ संघमित्रा गौतम, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्ध गोपाल वर्मा, जनपद पंचायत के सीईओ माया बारिया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में चर्चा और जल जीवन स्वच्छता अभियान पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जिसमें ग्राम पंचायत उदयगढ़ के व्यापारियों और जनता से सवाल कर उनकी समस्याएं जानी और समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। कार्यक्रम में किसान केसर सिंह चौहान ने बताया कि, मेरे खेत में लोगों का गंदा पानी आने से फसलों का नुकसान हो रहा है साथ ही उदयगढ़ बस स्टैंड पर बरसों पुराना हैंडपंप लगा हुआ है उसमे विगत 15 - 20 दिनों से नालियों का गंदा पानी रिसकर अंदर जा रहा है, जिससे हेडपंप का पानी पीने योग्य नहीं रहा। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने संज्ञान में लेकर पिएचई विभाग को आदेश किया कि इसका सैंपल लेकर इसकी जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

साथ ही कार्यक्रम में नालियों का पानी सड़कों पर आना, अतिक्रमण, दो नए आंगनबाड़ी भवन की मांग, हाट बाजार का मुद्दा उठाया गया। शुक्रवार को हाट बाजार का दिन होने से गांव के अंदर बसों का आना-जाना नहीं होता, इस बात को लेकर जिला पंचायत सीईओ मैडम को बताया कि 20-25 वर्षों से कृषि अनाज मंडी उदयगढ़ का उपयोग नहीं हो रहा है व्यापारियों के उपयोग नहीं आ रही है तो हाट बाजार कृषि अनाज मंडी में कर दिया जाए।

ठोस अपशिष्ट के लिए और पशु के अंतिम संस्कार हेतु करीबन 1 से 2 एकड़ जमीन उदयगढ़ के पटवारी से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती हीरा राजू मुवेल, डॉ. शब्बीर हामिदी, राजू डावर, शुभम राठौड़, चेतन राठौड़, नटवर, नरु, सलीम, केसर सिंह, दुकाल सिंह, मनीष परमार, मुकेश अजनार, बुट सिंह के साथ ग्रामीण उपस्थित रहे।

'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान

माही की गूंज, आलीराजपुर।

मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के निर्देशन में संचालित ÷नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0÷ जन-जागरूकता अभियान के चतुर्दश दिवस पर जिला आलीराजपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों, ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों तथा आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्त समाज निर्माण का संदेश दिया गया।

अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस कंट्रोल रूम, आलीराजपुर में सिंहस्थ प्रशिक्षण हेतु उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को राजयोग साधना केन्द्र से पधारी बहनों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों एवं नशामुक्त जीवन के महत्व की जानकारी प्रदान की गई तथा सभी को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई।

इसी क्रम में थाना आजाद नगर द्वारा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं को नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया गया। थाना चांदपुर द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं विद्यालय में छात्राओं एवं विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

थाना कठ्ठीवाड़ा द्वारा ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने हेतु प्रेरित किया गया तथा समाज में नशामुक्त वातावरण के निर्माण का संदेश दिया गया।

थाना जोबट द्वारा थाना परिसर में नागरिकों के मध्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नशे के दुष्परिणामों एवं उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति उमठ बघेल द्वारा खट्टाली कन्या शाला हाई स्कूल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छात्राओं को नशामुक्त जीवन के महत्व से अवगत कराते हुए जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त थाना बोरी द्वारा आमजन एवं थाना उदयगढ़ द्वारा थाना परिसर में उपस्थित नागरिकों को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज को नशामुक्त बनाने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपस्थित विद्यार्थियों, युवाओं एवं नागरिकों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा समाज में नशामुक्त वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिला पुलिस आलीराजपुर द्वारा अभियान के अंतर्गत आगामी दिनों में भी विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जाएंगे।

3 अगस्त से शुरू होंगी बाबा महाकाल की श्रावण-भादौ सवारियां

माही की गूंज, उज्जैन।

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती वृद्ध की मौत के बाद चरक अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में उस समय स्थिति असहज हो गई, जब परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इंकार कर दिया। पुलिस ने उन्हें काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, तब परिजन तैयार हुए।

माधवनगर थाना पुलिस ने बताया कि बडनगर निवासी मुबारिक (69) पुत्र कादिर हुसैन को परिजनों ने घायल अवस्था में निजी अस्पताल भर्ती करवाया था। उपचार के दौरान रात में वृद्ध की रविवार देर रात मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना माधवनगर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को निजी अस्पताल से चरक अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष पहुंचाया, जहां सोमवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम होना था। लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम का विरोध कर दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मुबारिक किसी दुर्घटना या विवाद का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि गिरने से उन्हें चोट लगी थी। उनका कहना था कि मौत सामान्य परिस्थितियों में हुई है और उन्हें किसी तरह की शिकायत या संदेह नहीं है। इसी कारण वे शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते।

पुलिस ने जताई मजबूरी

माधवनगर थाना पुलिस ने परिजनों को समझाया कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती मरीज की उपचार के दौरान मौत होने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य है, इसलिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

मांडू ने ओढ़ी कोहरे की चादर, सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम की जरूरत

माही की गूंज, मांडू।

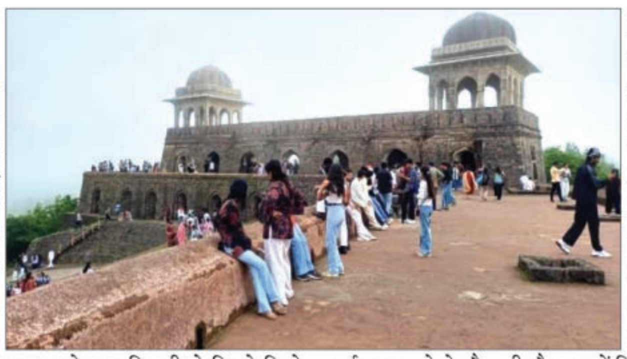

वर्षा के चलते मांडू का मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया है। यहां मानो जमीन पर स्वर्ग जैसे नजारे उतर आए हैं। पहाड़ियों से उठता घना कोहरा, हरियाली से लिपटे किले और बादलों को छूती ऐतिहासिक इमारतें देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। शनिवार को वीकेंड के चलते यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। रविवार को भी भीड़ बढ़ने के आसार है।

मांडू में इन दिनों मौसम बिल्कुल वैसा ही है, जिसकी उम्मीद यहां आने वाला हर सैलानी करता है। कभी हल्की, तो कभी तेज वर्षा और चारों ओर छाई हुई हरियाली ने यहां पर्यटकों के मांडू भ्रमण के आनंद को दोगुना कर दिया है। शनिवार सुबह से ही यहां पर्यटकों का आना शुरू हो गया था।

लगातार वर्षा के बाद मांडू की फिजा बदल गई है। कोहरे की चादर में लिपटी ऐतिहासिक इमारतें बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। रूपमती महल, जहाज महल, रेवा कुंड और बाज बहादुर पैलेस के आसपास का नजारा देखते ही बनता है। पर्यटक सेल्फी और फोटोग्राफी में जुटे हैं। सुहावने मौसम ने पर्यटन को बूस्ट दिया है। शनिवार को परिवार, कपल और युवा बड़ी संख्या में पहुंचे। टूरिस्ट गाइड यशवंत गावर का कहना है कि जैसा मौसम पर्यटक चाहते थे, वैसा ही मौसम उन्हें मिला। पर्यटक यहां ऐतिहासिक इमारतों के साथ मांडू के प्राकृतिक सुंदरता का भी जमकर लुत्फ ले रहे हैं।

धर्म, इतिहास, कला और संस्कृति का संगम

मांडू आने वाले पर्यटक सिर्फ नजारों के लिए नहीं, बल्कि यहां के धर्म, इतिहास, कला और संस्कृति को जानने भी आ रहे हैं। गाइड के जरिए लोग मांडू की शताब्दियों पुरानी कहानियों को समझ रहे हैं।

सुरक्षा और सुविधा जरूरी

भीड़ बढ़ने के साथ सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की जरूरत भी महसूस हो रही है। पार्किंग, पेयजल, शौचालय और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठ रही है। प्रशासन से अपेक्षा है कि वीकेंड को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए जाए, ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो।

शासकीय आईटीआई में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित

माही की गूंज, चशे आजाद नगर।

संचालनालय कौशल विकास मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सेजावाड़ा, चंद्रशेखर आजाद नगर (भाबरा), जिला आलीराजपुर में एक दिवसीय युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एक ही मंच पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था।

कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 03 कंपनियों ने सहभागिता की। इस दौरान 82 युवा उपस्थित हुए, जिनमें से 24 युवाओं का प्रारंभिक रूप से चयन कर उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किए गए। साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के प्रबंधक रोहित भिण्डे ने युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं तथा जिले के औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध भूखंड आवंटन संबंधी जानकारी देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।

गुरू पूर्णिमा पर कैबिनेट मंत्री ने किया गुरू पूजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष संतोष मकू परवाल तथा भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एवं विधायक प्रतिनिधि गोविंद गुप्ता, मंडल महामंत्री राजेश गुप्ता के साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और संत-महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया।

कार्यक्रम की शुरुआत शेषशाई आचार्य मंदिर से हुई, जहां सभी ने भगवान लक्ष्मी व्यंकटेश की की विधिवत आरती में भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्तिमय वातावरण के बीच भगवान का पूजन अर्चन कर जिले की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की गई। इसके पश्चात गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन कर गुरु-शिष्य परंपरा का सम्मान किया गया। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन को सही दिशा देने का कार्य करते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं का प्रतीक है।

इसके बाद सभी रामदेव मंदिर स्थित समाधि स्थल पहुंचे, जहां श्रद्धा एवं भक्ति के साथ महामंडलेश्वर नरसिहानंद जी महाराज एवं अन्य संतों की समाधि पर पूजा-अर्चना कर संतों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। यहां उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर प्रदेश की उन्नति, समाज में सुख-शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की गई।

इसके उपरांत सभी पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां संत श्री का विधिवत सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संतों ने सभी जनप्रतिनिधियों को धर्म, सेवा और समाजहित के कार्यों में निरंतर अग्रसर रहने का संदेश देते हुए जनकल्याण के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु केवल शिक्षा देने वाले नहीं, बल्कि जीवन को प्रकाशमय बनाने वाले मार्गदर्शक होते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि संतों का आशीर्वाद समाज को सकारात्मक दिशा देता है तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण हम सभी का दायित्व है।

पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भजन-कीर्तन, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजनों एवं संत-महात्माओं का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

अब जिला प्रशासन तय करेगा कि आप मुख्यमंत्री को शिकायती आवेदन दे सकते है या नहीं...?

सीएम के दौरे के दौरान शिकायती आवेदन देने पर जिला प्रशासन की रोक, भोपाल जाकर आवेदन देने की सलाह

माही की गूंज, झाबुआ।

कहते है कुआ प्यासे के पास नहीं आता बल्कि प्यासे को ही कुए के पास जाना पड़ता है। मगर जब किसी जल स्त्रोत की जलधारा प्यासे के पास पहुंच जाए और फिर भी उसे यह कहा जाए कि, नहीं यहां नहीं आपको अपनी प्यास जल स्त्रोत तक जाकर बुझानी होगी और बहती जलधारा पर नौकरशाही पूर्ण प्रतिबंध लगा देती है। तब कई सवाल खड़े होते दिखाई देते है। सीधी भाषा में अगर इसे समझे तो मां नर्मदा का उदगम स्थल अमरकंठक माना जाता है। वहां से चलकर नर्मदा देश और प्रदेश के कई हिस्सों से होकर बहती है, लेकिन तानाशाही अब इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को कहा जाता है कि आप यहां से नर्मदा जल नही ले सकते आपकी समस्या का समाधान यहां से नहीं होगा बल्कि आपको अमरकंठक जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। ऐसी ही कुछ हरकत जिला प्रशासन पिछले दिनों करता नजर आया।

पिछले दिनों 23 जुलाई को मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिले के सड़क मार्ग से होते हुए आलीराजपुर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो जिलेवासी अपनी समस्याओं और आवेदनों के साथ उस मार्ग तक पहुंचे जहां से मुख्यमंत्री गुजरने वाले थे। मगर हाय रे इन शिकायतकर्ताओं और आवेदकों की किस्तम कि बीच में ही जिला प्रशासन दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। सीएम को आवेदन देने पहुंचे लोगों को जिला प्रशासन की ओर से ऐसी बेतुकी सलाह दी जाती कि, आप यहां मुख्यमंत्री को आवेदन नहीं दे सकते। अगर आपको आवेदन देना है तो भोपाल जाईये...!

यह बिल्कुल वैसा ही है जैला हमने उपर उल्लेखित किया कि अगर नर्मदा जी का जल चाहिए तो आपको अमरकंठक जाने की सलाह मिलती है। 23 जुलाई को आजाद जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री का आलीराजपुर जिले का दौरा तय हुआ था। वे आलीराजपुर जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे। मुख्यमंत्री व्हाया सड़क मार्ग झाबुआ जिले से निकले। इसकी सूचना जब आम लोगों को मिली तो कई लोग उस सड़क मार्ग के किनारे अपनी समस्या और आवेदन लेकर पहुंच गए। सड़क मार्ग से होते हुए मुख्यमंत्री का काफिला कई जगह स्वागत सत्कार के लिए टुरिज्म मोटल पर रूका भी। जहा नेता तो स्वागत के लिए सीएम तक पहुचे लेकिन जिला प्रशासन ने इस पूरे सड़क मार्ग पर ऐसी योजना तैयार की थी कि जिले से कोई भी आवदेक मुख्यमंत्री को आवेदन नहीं दे सके। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं और आवेदन लेकर मिलने वाले लोगों को यह कहा गया कि, यहां मुख्यमंत्री जी को कोई आवेदन नहीं दिया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री को आवेदन देना ही है तो फिर भोपाल जाकर दें। प्रशासन की इस तरह की हरकत पर कई सवाल खड़े हो रहे है।

जिला प्रशासन ऐसा कैसे कर सकता है कि जब कुंआ ही प्यासे के पास पहुंचे और प्रशासन उस पर कड़ा पहरा लगाकर यह कहे कि, कुंआ भले ही यहां प्यासे के पास आया है मगर उन्हे प्यास बुझाने की इजाजत नहीं है। अगर उन्हे अपनी प्यास बुझानी है तो वे कुंए के पास भोपाल जाए और अपनी प्यास बुझाए।

मृतक रोहित की पत्नी ने प्रशासन के मना करने के बाद भी मुख्यमंत्री से मिली व आवेदन के साथ माही की गूंज का अखबार हत्या की वस्तु स्थिति जानने हेतु मुख्यमंत्री को दिया।

आखिर जिला प्रशासन ने ऐसा क्यों किया यह तो वो ही जाने, लेकिन जिले की जनता इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि, जिला प्रशासन ने इसलिए आवेदकों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया क्योंकि आखिर में बखिया तो प्रशासन की ही उधड़ना थी। जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान कतई नहीं चाहता था कि जिले से कोई आवेदन मुख्यमंत्री तक पहुंचे और जिला प्रशासन का सिर दर्द बने। इसीलिए जिला प्रशासन ने इसको लेकर पुख्ता इंतेजाम कर लिए कि मुख्यमंत्री तक इस दौरे के दौरान कोई आवेदक नहीं पहुंचना चाहिए। जिससे न रहेगा बांस और न बजेगी बांसूरी।

इसी कड़ी में पिछले दिनों जिले में हुए काकनवानी हत्या कांड के पीड़ित भी न्याय की उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री को इसी दौरे के दौरान आवेदन देने और बात करने पहुंचे थे। हालांकि जिला प्रशासन के टुरिज्म मोटल पर लाख रोकने के बावजूद भी वे मुख्यमंत्री को अपना आवेदन और न्याय की गुहार लगाने में सफल रहे। जब मुख्यमंत्री गेट के बाहर निकले तो मृतक रोहित पंचाल की पत्नी, मुख्यमंत्री को पति की मौत की जाच करने की मांग की व आवेदन के साथ 2 जुलाई का माही की गूंज अखबार भी मुख्यमंत्री को दिया जिसमें रोहित की हत्या का समाचार प्रकाशित हुआ था। मुख्यमंत्री ने मृतक की पत्नी को उच्चस्तरिय जाच करवाने का आश्वासन दिया साथ ही आर्थिक सहायता हैतु बैक अकाउंट नम्बर भी मांगा और न्याय का पूरा भरोसा भी पीड़ितों को दिलाया। मगर सवाल तो अब भी प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर हैं? आखिर क्यों लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी शिकायतें देने के लिए रोका जा रहा है। क्या जिला प्रशासन को कोई डर है जो वह जाहिर नहीं कर रहा है। या फिर जिले की परेशान आमजन जनता जिला प्रशासन के लिए कोई मायने नहीं रखती।

मुख्यमंत्री का 23 जुलाई का दौरा सिर्फ जिले के सड़क मार्गो से होते हुए आलीराजपुर के लिए गुजरा था। जिसको लेकर प्रशासन ने इस कदर कठोर इंतजाम किए थे कि, कोई शिकायती आवेदक मुख्यमंत्री तक न पहुंच सके। मगर अब आने वाली 31 जुलाई को मुख्यमंत्री का फिर से एक दौरा जिले में हो रहा है वे 31 जुलाई को पुनः जिले के थांदला में आ रहे है। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम थांदला के शासकीय महाविद्यालय कॉलेज मैदान पर होना है। वे यहां प्रदेश स्तरीय आजीविका महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित भी करेंगें।

अब देखना यह है कि, क्या जिला प्रशासन इस 31 जुलाई को होने जा रहे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी वैसी ही व्यवस्था करेगी, जैसी उसने 23 जुलाई के दौरे में की थी। यानि क्या इस बार भी यह तय है कि जिला प्रशासन आवेदकों और शिकायतकर्ताओं को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देगा? या फिर 31 जुलाई को जिले के आवेदक मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं और आवेदन दे सकेंगे। यह सब अभी समय के गर्त में है, लेकिन जिला प्रशासन का रवैया भी अभी स्पष्ट नहीं कि वह आवेदकों और शिकायतकर्ताओं को मुख्यमंत्री से मिलने देगा या नहीं? या यह भी हो सकता है कि माही की गूंज में छपी इस खबर के बाद प्रशासन अपने फैसले में फैर-बदल कर ले और आवेदकों और शिकायतकर्ताओं को मुख्यमंत्री से मिलने दें।

खैर जो भी हो लेकिन अब 31 जुलाई को कुंआ फिर प्यासों के पास आ रहा है तो ऐसा नही होना चाहिए कि, जिला प्रशासन प्यासों को कई सौ किलोमीटर दूर कुंए के पास जाने की सलाह दे दे। जिले के आवेदकों और शिकायतकर्ताओं के पास भी यह एक अच्छा अवसर है कि वे अपनी बात, अपने जिले में खड़े होकर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से करें। मगर जिला प्रशासन का इसको लेकर क्या रवैया रहेगा इस पर अभी तक तो प्रश्न चिन्ह ही है।

त्वरित टिप्पणी: नशे से दूरी के साथ नेटवर्क पर निगरानी और कार्रवाई की जरूरत

दूसरे राज्य की पुलिस को तलाश स्थानीय स्तर के आरोपियों की, हमारे यहां नारों से जनजागरूकता की बात

माही की गूंज, झाबुआ।
धर्मेंद्र पंचाल

मध्यप्रदेश पुलिस के निर्देश पर झाबुआ पुलिस इन दिनों पूरे उत्साह के साथ ''नशे से दूरी 2.0'' अभियान चला रही है। जगह-जगह पोस्टर लग रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, युवाओं को शपथ दिलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर संदेशों की भरमार है। तस्वीरें बता रही हैं कि अभियान पूरे जोश से चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभियान केवल तस्वीरों और नारों तक सीमित है, या जमीनी स्तर पर भी उसकी उतनी ही गूंज सुनाई दे रही है?

बीते एक सप्ताह में दो बार गुजरात पुलिस ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करते हुए झाबुआ जिले के थांदला पहुंची। इसका सीधा अर्थ है कि जांच की कड़ियां यहां तक जुड़ रही थीं। दूसरे राज्य की पुलिस को सुराग मिले, संदिग्धों तक पहुंचने का रास्ता मिला और कार्रवाई के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर आना पड़ा। लेकिन स्थानीय पुलिस के लिए यह सब मानो किसी दूसरे ग्रह की घटना हो। न कोई पूर्व जानकारी, न कोई स्थानीय कार्रवाई और न ही ऐसा कोई संकेत कि यहां पहले से कोई सक्रिय जांच चल रही थी।

आखिर यह कैसे संभव है कि बाहर की पुलिस को जिले के भीतर तक आने का रास्ता मिल जाए, लेकिन स्थानीय तंत्र को भनक तक न लगे? क्या अपराधी केवल दूसरे राज्यों की पुलिस को दिखाई देते हैं? या फिर हमारी व्यवस्था की आंखें तभी खुलती हैं, जब कोई बाहरी एजेंसी दरवाजा खटखटाती है?

यह पहली बार नहीं है जब किसी दूसरे राज्य की पुलिस ने झाबुआ में आकर कार्रवाई की हो। समय-समय पर ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। हर बार

सवाल वही रहता है कि यदि नेटवर्क यहां तक फैला हुआ है, तो स्थानीय खुफिया व्यवस्था क्या कर रही थी? क्या मुखबिर तंत्र केवल कागजों में सक्रिय है? क्या स्थानीय निगरानी केवल औपचारिकता बनकर रह गई है?

विडंबना देखिए, मंचों से कहा जाता है कि ''नशे के खिलाफ जन-जागरण जरूरी है।'' यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जनता भी पूछ रही है कि जागरूकता के साथ-साथ कार्रवाई कब दिखाई देगी? क्योंकि नशे का कारोबार केवल भाषणों से नहीं रुकता। उसके लिए लगातार सूचना संकलन, आर्थिक नेटवर्क पर निगरानी, तस्करी के मार्गों की पहचान और समय रहते कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

आज स्थिति यह है कि, अभियान के फोटो रोज दिखाई देते हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई की खबरें अक्सर दूसरे राज्यों की पुलिस के माध्यम से आती हैं। इससे यह संदेश भी जाता है कि कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है। यदि पड़ोसी राज्य की पुलिस यहां तक पहुंच सकती है, तो स्थानीय पुलिस उससे एक कदम आगे क्यों नहीं हो सकती?

यह समाचार झाबुआ पुलिस विभाग की सफलता या असफलता की तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि एक जरूरी प्रश्न उठाने के लिए है। यदि झाबुआ वास्तव में ''नशे से दूरी'' अभियान को सफल बनाना चाहता है, तो सबसे पहले नशे के नेटवर्क से दूरी नहीं, बल्कि उसके खिलाफ नजदीकी निगरानी और कठोर कार्रवाई जरूरी होगी।

अभियानों की सफलता पोस्टरों की संख्या से नहीं, बल्कि पकड़े गए तस्करों, ध्वस्त किए गए नेटवर्क और सुरक्षित हुए युवाओं से मापी जाती है। जनता को नारों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब उसे नारों के साथ परिणाम भी चाहिए।

आखिरकार, यदि हर बार दूसरे राज्य की पुलिस झाबुआ आकर ड्रग्स की कड़ियां खोजे और स्थानीय तंत्र कहे कि ''हमें तो जानकारी ही नहीं थी'' तो ''नशे से दूरी'' अभियान का सबसे बड़ा लाभ शायद नशा तस्करों को ही मिलता दिखाई देगा।

स्कूल भवन जर्जर बच्चे निजी मकान में अध्यनरत पर संकुल प्राचार्य अनभिज्ञ

माही की गूंज, खवासा।
सुनिल सोंलकी

डबल इंजन की सरकार में विकास के कई दावे तो किए जाते हैं लेकिन जब धरातल पर इन्हीं विकास की जांच पड़ताल की जाए तो कई तरह की अनियमितताओं का अंबार दिखाई देता है।

खवासा क्षेत्र की बात करें तो यहां ग्रामीण अंचल में कई स्कूल भवन जर्जर है और बच्चे भी उस भवन में बैठने की स्थिति में न होकर निजी मकान में स्कूल का संचालन हो रहा है। और संकुल क्षेत्र के प्राचार्य मामले में पूरी तरह अनभिज्ञता दिखाते हैं तो उस क्षेत्र व जिले की शिक्षा प्रणाली व उसकी व्यवस्था किस स्तर की होगी यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

खवासा कन्या संकुल के अंतर्गत भेरूगढ़ ग्राम पंचायत के छोटी रामगढ़ में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की बात करें तो यह पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। जब हमारे प्रतिनिधि को आम लोगों द्वारा जानकारी देने के बाद छोटी रामगढ़ की प्राथमिक शाला की वस्तुस्थिति की जानकारी निकाली तो सामने आया कि, यहां का भवन पूरी तरह से जर्जर है। पानी की व्यवस्था नहीं है और न ही यहां शौचालय की व्यवस्था है। वही मजबूरी में पदस्थ शिक्षक निजी अन्य मकान में बच्चों को बिठाकर पढाने को मजबूर है।

इस संबंध में जब पदस्थ शिक्षक मांगूलाल भाभर से बात की तो बताया कि, स्कूल में 81 बच्चे कुल भर्ती है जिसमें से प्रतिदिन 70 के करीब बच्चों की उपस्थिति रहती है। बच्चे पानी पीने के लिए दूसरे कुएं से या घर से पानी भरकर लाते हैं। जो भवन यहां प्राथमिक शाला के है वह पूरी तरह से जर्जर होकर डिसमेंटल स्थिति में है। बच्चों के साथ कोई आकस्मिक जर्जर भवन की स्थिति में कोई दुर्घटना न हो जाए इसलिए बच्चों को गांव के एक अन्य निजी मकान में बिठाकर पढ़ाई कराई जा रही है।

मांगूलाल भाभर ने बताया कि, जनशिक्षक से लेकर संकुल प्राचार्य व उच्च अधिकारियों को उक्त समस्या के संबंध में कई बार अवगत करवाया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं शिक्षक ने बताया कि, जर्जर स्कूल भवन के पास हेडपंप लगाया गया है जर्जर भवन व हेडपंप के संबंध में ग्राम पंचायत को भी अवगत करवाया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा हेडपंप को खोलकर उसमें सभी पुराने पाइप सुधार हेतु निकाल लिए लेकिन काफी समय होने के बाद भी नए पाइप न हीं ग्राम पंचायत उपलब्ध करवा पाई न ही विभाग।

वहीं ग्रामीणों ने माही की गूंज को बताया कि, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन की उक्त अनियमितता व अनदेखी क्षमा योग्य नहीं है। प्रशासन को यहां त्वरित नए भवन की मंजूरी देकर व्यवस्थाओं को सुचारू करना चाहिए।

मामले में जब संकुल प्राचार्य श्री राजपत से बात की तो बताया, मुझे जर्जर भवन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। प्राचार्य ने यहां तक बताया कि, संकुल में आने वाले किसी भी भवन के संबंध में हमारा कोई लेना-देना हमारे कार्य में नहीं आता है। हमारा काम संकुल क्षेत्र में आने वाले शिक्षकों का वेतन निकलवाना व उनके द्वारा कोई पत्र समस्या संबंधी हमें दिया जाता है वह पत्र वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना हमारा कार्य है।

जब आचार्य से पूछा कि क्या छोटी रामगढ़ में पदस्थ शिक्षक ने आपको कोई जर्जर भवन के संबंध में पत्र दिया? तो प्राचार्य ने मना करते हुए बताया कि, मुझे जर्जर भवन की कोई जानकारी नहीं है।

हैडपंप से निकाले पाइप नही डाले, पाईप की जगह डाल रखा लकड़ा।

पुरी तरह से जर्जर व अनुपयोगी भवन।

तीन पंचायतों ने नकारा गौराबाई आदिवासी नहीं, जांच में सामने आया एसटी जाति का बड़ा खेल

आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए चल रहा है बड़ा खेल

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

पिछले दिनों मनावर क्षेत्र से विधायक हीरालाल अलावा ने विधानसभा में आदिवासियों की जमीन सामान्य वर्ग को हस्तांतरित करने का गंभीर मुद्दा उठाया था। सरकारी रिकॉड में हेरा फेरी ओर दस्तावेजों का हेर फेर इन बेशकीमती जमीनों के आदिवासीयों से अन्य वर्ग के नाम होने का खेल कई आदिवासी जिलों में खेला जा रहा है, लेकिन कोई आदिवासियों की जमीन हथयाने के लिए अन्य वर्ग का व्यक्ति खुद के जाति में परिवर्तन कर खुद आदिवासी का प्रमाण पत्र बनवा कर जमीन खरीद के रजिस्ट्री करवा के अपने नाम करवा ले ये बड़ा मामला झाबुआ जिले के पेटलावद विकास में सामने आया है, जहा एक परिवार ने अपने ही परिवार की एक महिला को आदिवासी वर्ग का बता कर गांव के आसपास आदिवासियों की जमीन खरीद कर अपने नाम करवा ली। मामला वर्षो से जांच के नाम पर लंबित चलता रहा ओर जांच के दौरान भी जमीन की खरीद फरोख्त होती रही, विवाद हुए ,मामला पुलिस के पास ओर तहसील कार्यालय से लेकर एसडीएम, कलेक्टर, सीएम हेल्पलाइन से लेकर हाईकार्ट तक पहुंचता रहा लेकिन मामले की सही जांच नहीं होने से विवाद की स्थिति बढ़ गई । आखिर न्यायालय के निर्देश के बाद मामले की जांच में तेजी आई ओर जो जांच रिपोर्ट सामने आई उसने सबको चैका दिया, मामला पूरी तरह से फर्जी जाति का निकला । हालांकि माही की गूंज ने पूर्व में भी इस मामले में खुलासा किया था लेकिन प्रशासन ने कोई खास ध्यान नहीं दिया ओर भेट पूजा ओर बार बार बदलते बयानों के चलते मामले को फाइल बना कर घुमाया गया ।

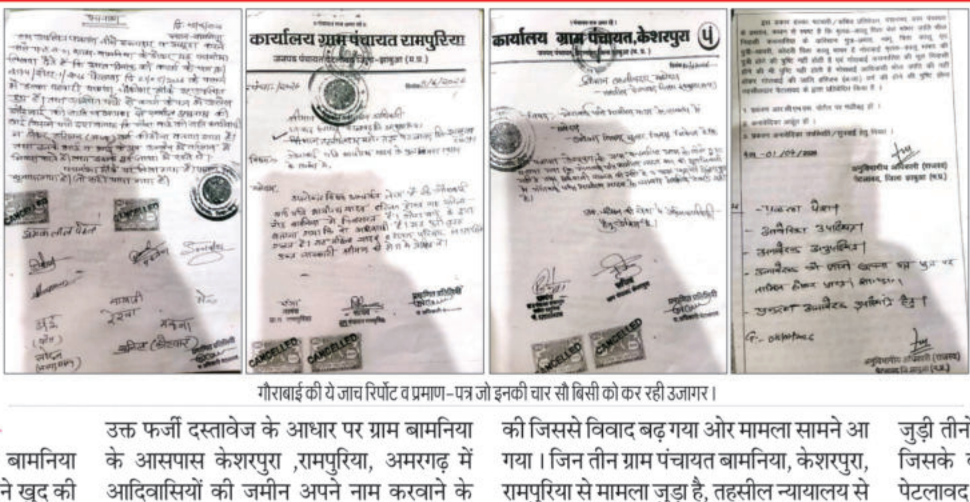
गौराबाई की ये जाच रिर्पोट व प्रमाण-पत्र जो इनकी चार सौ बिसी को कर रही उजागर।

तीन पंचायतों से जुड़ा मामला

पेटलावद विकास खंड के ग्राम बामनिया निवासी रिटायर्ड शिक्षक भगीरथ यादव ने खुद की पत्नी गौराबाई यादव को बामनिया के समीप ग्राम पंचायत केशरपुरा की निवासी बताते हुए उसे आदिवासी परिवार की बताया, बकायदा आधार कार्ड में पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम लिखा गया ओर जाती भील आदिवासी बताई गई, उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर ग्राम बामनिया के आसपास केशरपुरा ,रामपुरिया, अमरगढ़ में आदिवासियों की जमीन अपने नाम करवाने के लिए भगीरथ यादव ने पत्नी गौराबाई के नाम का सहारा लिया ओर एक दो जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली , रजिस्ट्री होने के बाद से मामले की शिकायत हुई ओर जांच चलती रही । इस दौरान भगीरथ यादव ने ओर जमीन खरीदने की कोशिश की जिससे विवाद बढ़ गया ओर मामला सामने आ गया । जिन तीन ग्राम पंचायत बामनिया, केशरपुरा, रामपुरिया से मामला जुड़ा है, तहसील न्यायालय से जारी नोटिस के बाद तीनों पंचायतों में ग्राम पंचायत,पटवारी ने जांच की पंचनामा तैयार किया, केशरपुरा पंचायत के कचनारिया निवासी कालू भाभर की वंशावली तैयार की गई ओर उसमें खुलासा हुआ कि गौराबाई पति भागीरथ ग्राम कचनारिया की नहीं है न ही कालू भाभर की लड़की है, राखी डोरे के रिश्ते को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वंशज बनाया गया ओर फिर आदिवासियों की जमीन अपने नाम करवाने का खेल शुरू हुआ।

तहसील न्यायालय की जांच में गौराबाई यादव को एसी वर्ग होना पाया गया

पूरे मामले की जांच अनुविभागीय न्यायालय में चल रहे मामले में तहसील न्यायालय के माध्यम से चल रही थी ,जांच में सभी पक्षों सहित मामले से जुड़ी तीनों पंचायतों के भी बयान दर्ज किए गए । जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद ने निर्णय देते हुए गौराबाई पिता कालू भाभर को कालू भाभर की पुत्री नहीं मानते हुए साफ किया कि गौराबाई कचनारिया निवासी की पुत्री नहीं होकर गौराबाई आदिवासी वर्ग की नहीं है ओर गौराबाई अजा वर्ग की होना पाया गया है। उक्त निर्णय के बाद आदिवासी अंचल में आदिवासियों की जमीन हतयाने के लिए तरह-तरह के फर्जीवाड़े कर फर्जी दस्तावेज, शपथ पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तैयार किए जा रहे है। एसआईआर जैसी पहल में ये फर्जीवाड़ा पकड़ा नहीं गया जिससे सभी सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठते है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद की।

कार्रवाई कब ओर क्या

लंबे समय से जांच के नाम पर अटके मामले में जांच होने के बाद निर्णय आ चुका है और लगभग बीस दिन से ज्यादा हो चुके है। लेकिन इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। जमीन की रजिस्ट्री से लेकर नामांतरण, और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालो के साथ-साथ फर्जी दस्तावेज के आधार पर खुद को आदिवासी बनाने वाली गौराबाई ओर उसके पति भागीरथ यादव पर कोई कार्रवाई न तो की गई न ही किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया। शिकायतकर्ता ओर पीड़ित परिवार अब इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे है। ताकि भविष्य में इस प्रकार से आदिवासियों की जमीन ओर उनके अधिकार छीनने का कोई प्रयास नहीं करे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422